



रक्षा, एयरोस्पेस और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर छत्तीसगढ़



मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य तेजी से तकनीकी नवाचार, आधुनिक उद्योगों और रणनीतिक क्षेत्रों का नया केंद्र बन रहा है। रक्षा, एयरोस्पेस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए लागू विशेष प्रोत्साहन नीति राज्य को नई पहचान और अपार संभावनाओं की ओर ले जा रही है।

छत्तीसगढ़ का नया विजन

युवा बनेगा परिवर्तन की शक्ति

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सोच है कि छत्तीसगढ़ का युवा केवल रोजगार तलाशने वाला न रहे, बल्कि उद्योग और स्टार्टअप स्थापित कर दूसरों को रोजगार देने वाला बने। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में आधुनिक उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से राज्य सरकार युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ रही है। इससे छत्तीसगढ़ अब पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़ते हुए हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में नई पहचान बना रहा है।

रक्षा, एयरोस्पेस और स्पेस उद्योगों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज

- ✓ स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर कर लाभ और पूंजी अनुदान
- ✓ ब्याज अनुदान, बिजली शुल्क में छूट और भूमि संबंधी सुविधाएं
- ✓ स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क और भूमि उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन) शुल्क में रियायत
- ✓ स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर विशेष प्रोत्साहन राशि
- ✓ बड़े निवेश करने वाली इकाइयों को अतिरिक्त औद्योगिक लाभ

स्पेस टेक्नोलॉजी से राज्य को व्यापक लाभ

- कृषि क्षेत्र में सटीक फसल पूर्वानुमान, मिट्टी की गुणवत्ता सुधार और जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन
- बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रणाली और त्वरित प्रतिक्रिया
- नगर नियोजन, परिवहन व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में स्पेस डेटा का उपयोग
- वन क्षेत्रों की निगरानी और अवैध कटाई की रोकथाम के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग
- पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और प्रदूषण नियंत्रण में तकनीकी सहायता



स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और अनुसंधान को प्राथमिकता

नई नीति में स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार देने वाली इकाइयों को विशेष सहायता दी जा रही है। रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ड्रोन प्रशिक्षण संस्थान और अत्याधुनिक तकनीकी परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।



स्थायी रोजगार



अनुसंधान और नवाचार



कौशल विकास



स्टार्टअप प्रोत्साहन

इसरो के साथ साझेदारी से विकास को नई गति

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की इसरो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठकों के बाद छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष तकनीक के उपयोग को नई दिशा मिली है।

- सेटेलाइट आधारित सर्वेक्षण और भू-मानचित्रण
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन
- स्मार्ट कृषि और जल प्रबंधन को बढ़ावा
- आपदा प्रबंधन के लिए आधुनिक चेतावनी प्रणाली
- डेटा विश्लेषण और जीआईएस तकनीक का उपयोग



उद्योग और निवेश : नई ऊंचाइयों की ओर

रक्षा, एयरोस्पेस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में देश-विदेश की बड़ी कंपनियों की रुचि लगातार बढ़ रही है। इससे राज्य में निवेश के नए अवसर बन रहे हैं, औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं और हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यह नीति 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना को छत्तीसगढ़ में मजबूत कर रही है।



अनुसंधान संस्थानों और युवाओं को नया मंच

राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को इस पहल से जोड़ा है। इससे हजारों छात्र, शोधकर्ता और युवा वैज्ञानिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचारों में योगदान देकर राज्य के विकास में भागीदार बन रहे हैं। यह सहयोग छत्तीसगढ़ को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और भविष्य के अनुरूप बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।



श्रमिक कल्याण : सरकार की संवेदनशील और समर्पित पहल

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिये लाखों श्रमिक परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, मातृत्व सहायता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य है - हर श्रमिक सम्मानित हो, सुरक्षित हो और आत्मनिर्भर बने।

सरकार का संकल्प

काम, सम्मान और सुरक्षा हर श्रमिक का अधिकार

- ✓ हर हाथ को काम का अवसर
- ✓ मेहनत का उचित सम्मान
- ✓ हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा
- ✓ बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर
- ✓ भोजन और आवास की सुविधा

मोबाइल कैंप से पंजीकरण अभियान को मिली गति

असंगठित श्रमिकों और निर्माण कर्मचारियों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए राज्यभर में मोबाइल कैंप लगाए जा रहे हैं। अब तक हजारों कैंप आयोजित किए गए, जिनसे बड़ी संख्या में श्रमिकों का पंजीकरण हुआ और वे योजनाओं से जुड़ सके।



श्रमिक परिवारों के लिए प्रमुख योजनाएं

- ✓ मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
- ✓ मिनीमाता महतारी जतन योजना
- ✓ मुख्यमंत्री श्रमिक औजार किट योजना
- ✓ मुख्यमंत्री नोवी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना
- ✓ निःशुल्क गणवेश एवं अध्ययन सामग्री सहायता योजना
- ✓ उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना
- ✓ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना
- ✓ शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना

श्रम अन्न योजना का विस्तार

राज्य सरकार द्वारा संचालित श्रम अन्न योजना प्रदेश के अनेक जिलों और औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। यह योजना हजारों श्रमिकों को रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रही है।



संवाद-48873/1

नया छत्तीसगढ़, नई पहचान

- ✓ उच्च तकनीक, नवाचार और निवेश का केंद्र
- ✓ युवाओं के लिए रोजगार और करियर के अपार अवसर
- ✓ कृषि, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में तकनीकी क्रांति
- ✓ श्रमिकों के कल्याण और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध सरकार
- ✓ विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर कदम



छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, तकनीक और संवेदना के साथ - विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की ओर...

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका को लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष शांडिल्य ने वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से सोमवार को लोकभवन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सुश्री रीता शांडिल्य ने मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026

तक की अवाधि का पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन श्री डेका को सौंपा। इस अवसर पर रण्य लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉ. प्रवीण वर्मा, डॉ. सरिता उडके, श्री संतकुमार नेताम, श्री डी राहुल वेंकट, श्री चंद्र कुमार अजगले, श्री एच एल ध्रुव एवं श्रीमती लीना कोसम उपस्थित थीं।

शिक्षा रत्न सम्मान-2026 समारोह आज, कल्याण संघ द्वारा किया जा रहा आयोजन

रायपुर। निजी महाविद्यालय प्राचार्य कल्याण संघ, छत्तीसगढ़ द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर 1 सितंबर को शिक्षा रत्न सम्मान-2026 समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के प्रोफेसर डॉ. राजीव चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त करने पर सम्मान एवं अभिनंदन किया जाएगा। इस अवसर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट, सर्मापित एवं उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को उनके शैक्षणिक, सामाजिक एवं अकादमिक योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। संघ के सचिव डॉ. देवाशीष मुखर्जी ने बताया गया कि शिक्षक समाज के निर्माण और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों के ज्ञान, कर्मठता, अनुशासन, शैक्षणिक प्रतिबद्धता एवं प्रेरणादायी व्यक्तिव को सम्मान देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। समारोह में चयनित शिक्षकों को शिक्षा रत्न सम्मान-2026 से अलंकृत कर सम्मान-पत्र प्रदान किया जाएगा।

महाराष्ट्र मंडल ने रिमझिम बारिश

के बीच मनाया सावन उत्सव

रायपुर। महाराष्ट्र मंडल के महिला केंद्रों में इन



दिनों सावन उत्सव धूम मची हुई है। मंडल के सुंदर नगर केंद्र की महिलाओं ने समता कॉलोनी स्थित दिव्यांग बालिका विकास गृह- सियान गुड़ी में सावन उत्सव धूमधाम के साथ मनाया। रिमझिम फुहारों के बीच सबकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को आनंदमय बना दिया। बताते चलें कि मराठी समाज का सावन मास 12 अगस्त को हरेली अमावस्या के दूसरे दिन यानी 13 अगस्त से शुरू हुआ है, जो 11 सितंबर को श्रावणी अमास्या के साथ खत्म होगा। सुंदर नगर केंद्र की संयोजिका सिमता टेंबे ने बताया कि सावन उत्सव की शुरुआत महिलाओं के हाथों में छाता लेकर रिमझिम फुहारों के बीच दिव्यांग बालिका विकास गृह यानी कार्यक्रम स्थल में प्रवेश के साथ ही हुआ। महिलाएं एक के पीछे एक बिल्कुल रैंप वाक करते हुए आते रहीं। फिर महिलाओं का स्वागत हल्दी कुंकू लगाकर और वाण देकर किया गया। सह संयोजिका यशस्वी दंडवते के अनुसार महिलाओं ने रैंप वाक करते हुए बारिश और सावन को लेकर कई मजेदार डांस प्रस्तुत किए। हरी साड़ी के ड्रेस कोड में पहुंची महिला सभासदों के बीच हुई रोचक स्पर्धा में सुष्मा को सावन क्वीन चुना गया। हाथों में छाता लेकर गाना गाने वाले गेम में प्राची शिवनकर और साक्षी जोशी विजयी रहीं। वहीं सोलह श्रृंगार स्पर्धा में अंकिता किर्कवई विजेता रहीं।

इदवारा बैराज के सर्वेक्षण कार्य के लिए 2.66 करोड़ मंजूर

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग ने बीजापुर जिले के विकासखंड भैरमगढ़ में सिंचाई सुविधाओं को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित इदवारा बैराज के सर्वेक्षण कार्य के लिए शासन द्वारा 2 करोड़ 66 लाख 70 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस सर्वेक्षण कार्य के पूरा होने से क्षेत्र में जल भंडारण क्षमता और सिंचाई रकबे का सही आकलन हो सकेगा। इस परियोजना के आगे बढ़ने से स्थानीय किसानों को खेती-किसानी के लिए पर्याप्त जल मिलेगा, जिससे बीजापुर जिले के ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

पुरानी रंजिश को लेकर मां-बेटे पर हथौड़े से हमला, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर। जोरापारा में पुरानी रंजिश को लेकर मां-बेटे पर हथौड़े से हमला करने वाले आरोपी चिट्ठू साहू उर्फ धीरज के खिलाफ मोदहापारा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घायल मां-बेटे का इलाज अंबेडकर अस्पताल में चल रहा है। घटना 29 अगस्त की सुबह काली मंदिर के पीछे की बताई जा रही है। शिकायतकर्ता दितेश सोनवाने ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए पुलिस को बताया कि वह काली मंदिर के पीछे मौजूद था। इसी दौरान आरोपी चिट्ठू साहू उर्फ धीरज वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने दितेश के चेहरे पर हथौड़ी से वार कर दिया। बेटे पर हमला होते देखकर उसकी 65 वर्षीया मां सुशीला सोनवाने बीच-बचाव करने पहुंचीं।

झीरम घाटी कांड पर सीएम साय का भूपेश बघेल पर पलटवार

कहा- जेब में प्रमाण लेकर घूमने की बात करते थे

रायपुर। झीरम घाटी कांड में एनआईए की जांच पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सवाल उठाए जाने पर सीएम साय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहे। उस दौरान झीरम का प्रमाण जेब में लेकर घूमने की बात करते थे। वे सिर्फ बोलते रह गए, उन्हें मुख्यमंत्री रहते कुछ करना था।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि झीरम घाटी में कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को खोया। भूपेश बघेल को चिंता होती तो 5 साल में कुछ ना कुछ करते। वहीं सशस्त्र माओवाद समाप्त होने के बाद नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के सवाल पर



कहा कि इसके लिए कमेटी समीक्षा करती है। किसी की भी सुरक्षा के लिए जो आवश्यकता होती है, उसे कमेटी की सिफारिश पर मुहैया कराया जाता है।

बता दें कि कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने बस्तर पहुंचे

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी मामले में एनआईए कोर्ट का फैसला आने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हट्टू की जांच पर सवाल उठाए चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि न तो एफआईआर में नामजद लोगों से पूछताछ नहीं की गई और न ही मौके पर मौजूद लोगों के बयान लिए गए।

उन्होंने घटना के षड्यंत्रकारियों तक पहुंचने की दिशा में जांच नहीं होने की बात कहते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने भी मामले की आगे जांच के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिससे लगता है कि भाजपा मामले को दबाना चाहती है।

क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स रोड शो के लिए चुना गया छत्तीसगढ़

■ सीएम साय ने केंद्र का जताया आभार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स रोड शो के लिए छत्तीसगढ़ को चुनने पर केंद्र का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मिनरल्स के मामले में हमारा आत्मनिर्भर होना जरूरी है। क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम मिनरल्स का इस्तेमाल हथियार में कर रहे हैं। रक्षा उद्योग के लिए स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का उपयोग होता है। आज एआई, क्वीन एनर्जी समेत मेन्युफैक्चरिंग का दौर है। इसके लिए हमें क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। इसमें छत्तीसगढ़ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में 5 मिनरल्स क्रिटिकल की नीलामी हो रही,

यह स्वर्णिम अवसर है। सोने-चांदी से भी महंगे क्रिटिकल मिनरल्स हो गए हैं। यह छत्तीसगढ़ को नए क्षितिज पर ले जाएगा। यह देश ही नहीं बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ में हमारा लक्ष्य केवल खनिज उपकरण बढ़ाना नहीं, बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स को भी बढ़ावा देंगे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नई उद्योग नीति के तहत भी इन उद्योगों को महत्वपूर्ण जगह दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के निवेशकों को आने वाले दिनों में लाभ होगा। खनिज से राजस्व ढाई साल में 12 हजार करोड़ से बढ़कर 16 हजार करोड़ हो गया। देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। इसके साथ ही उन्होंने नीलामी में भाग लेने उद्योगपतियों से अपील की।

छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता है। निवेशक यहां आकर प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं।

पहली बारिश में पुल क्षतिग्रस्त, गुणवत्ता खराब मिली तो जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई: नेताम

■ कांग्रेस के आदिवासी आंदोलन पर साधा निशाना

रायपुर। बलरामपुर में ग्राम सड़क योजना के तहत बनाए गए पुल के पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया।इस मामले में मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि मामले की पूरी जानकारी आने दीजिए। मैं उस वक उपस्थित नहीं था। मंत्री ने गुणवत्ता को लेकर स्पष्ट कहा कि यदि कहीं भी निर्माण कार्य की स्थिति खराब पाई जाती है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी।

किसान मोर्चा की बैठक को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि भाजपा संगठन ने अलग-अलग मोर्चों की व्यवस्था की है। इन मोर्चों के माध्यम से संबंधित वर्गों के विषयों पर संगठन लगातार चिंता और अध्ययन करता है। पार्टी का उद्देश्य संगठन को सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बनाना है।

मंत्री नेताम ने कहा कि किसान मोर्चा के माध्यम से किसानों के बीच



उपलब्धियों, दायित्वों और समस्याओं का समय-समय पर अध्ययन किया जाता है। इसके बाद संबंधित रिपोर्ट संगठन को सौंपी जाती है। किसान मोर्चा की मांगों के आधार पर सरकार बनने के बाद किसानों से 2100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी शुरू की गई। इसके साथ ही अधिकतम उत्पादन लेने के प्रयास किए गए और वर्ष 2023 में सरकार बनने से पहले का बकाया बोनास भी किसानों को दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन का दायित्व है कि किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई

जाएं।

कांग्रेस द्वारा आदिवासी मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी के सवाल पर रामविचार नेताम ने कहा कि विपक्ष की अपनी भूमिका होती है और अलग-अलग समय पर विपक्ष अलग-अलग वर्गों के बीच जाता है। कांग्रेस कभी किसानों, कभी महिलाओं और कभी युवाओं के बीच जाने की दांव करती है और अब उसे एसटी वर्ग दिखाई दे रहा है, इसलिए आदिवासी समाज के बीच जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता और एसटी वर्ग के लोग कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते।

झीरम घाटी मामले को लेकर मंत्री नेताम ने कहा कि यह मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर वह क्या कह सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाई समय-समय पर उजागर होती रहती है और हाल के दिनों में भी कांग्रेस नेताओं के कई बयान सामने आए हैं।

झीरम घाटी हत्याकांड पर फैसला आने से पहले कांग्रेस में हलचल

भूपेश बघेल ने एनआईए जांच पर उठाए सवाल

रायपुर। बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड मामले में एनआईए कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी है। आज 31 अगस्त को फैसला आने की संभावना थी, लेकिन आज सुनवाई के बाद एनआईए कोर्ट ने फैसले की तारीख आगे बढ़ा दी है। लेकिन फैसला आने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनआईए की जांच पर सवाल उठाए दिए हैं।

बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि ऋद्धक में नामजद लोगों से पूछताछ नहीं की गई और मौके पर मौजूद कई लोगों के बयान भी नहीं लिए गए। उन्होंने कहा कि घटना के पीछे के षड्यंत्रकारियों तक पहुंचने की दिशा में जांच नहीं हुई।

बघेल ने बताया कि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री से जांच राज्य सरकार को सौंपने की मांग की थी। एसआईटी गठित करने पर एनआईए हाईकोर्ट पहुंच गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने भी मामले की आगे जांच के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिससे लगता है कि भाजपा मामले को दबाना चाहती है। इसके पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस



सिंहदेव ने भी घटनाक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वे खुद इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, और जगदलपुर पहुंचकर एनआईए के सामने अपनी आंखों देखी घटना का बयान दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन पूरे इलाके में पुलिस की मौजूदगी लगभग शून्य थी। रास्ते में कहीं भी पर्याप्त फोर्स तैनात नहीं थी. उन्होंने कहा कि उनके बयान में घटना से जुड़े सभी अहम पहलुओं को दर्ज कराया गया है। अगर जांच और फैसले में इन तथ्यों को जगह मिलती है, और इस घटना के लिए जिम्मेदारी भी तय होती है, तभी पीड़ितों और कांग्रेस नेताओं को न्याय मिलने का संतोष होगा।

शहीद वीर नारायण सिंह का जीवन सेवा, संघर्ष और राष्ट्रप्रेम की मिसाल : अरुण साव



प्रेम था। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में गरीब और शोषित लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। अंग्रेजों के अत्याचार के सामने वे कभी नहीं झुके और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।

श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती अनेक वीर योद्धाओं और जननायकों की गौरवशाली भूमि रही है। शहीद वीर नारायण सिंह और गुंडुधर जैसे महान योद्धाओं ने अपने साहस से समाज व मातृभूमि के प्रति समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। इन वीर सपूतों का त्याग और बलिदान हमारी आने वाली पीढ़ियों

को सदैव याद रहेगा। उन्होंने कहा कि बेमेतरा में स्थापित शहीद वीर नारायण सिंह की यह प्रतिमा उनके त्याग और बलिदान की स्मृति को चिरस्थायी बनाएगी। यह प्रतिमा युवाओं को राष्ट्रसेवा और समाजसेवा के लिए आगे बढ़ने का संदेश देगी। उन्होंने कहा कि देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले महापुरुषों का सम्मान हमारी जिम्मेदारी है।

केन्द्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ के अध्यक्ष श्री कमलेश सोरी, सर्व आदिवासी समाज जिला अध्यक्ष श्री मुरीत मंडावी, गोंड समाज जिला अध्यक्ष श्री दरबार सिंह नेताम, बेमेतरा नगर पालिका के अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा, उपाध्यक्ष श्री अशोक शर्मा, पूर्व विधायक श्री अवधेश चंदेल और श्री अजय साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गोंड समाज के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक भी आदिवासी महासम्मेलन में मौजूद थे।

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेस-1 में जलभराव से रहवासी परेशान

■ नालियों की सफाई और बेहतर जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग

रायपुर। राजधानी रायपुर के सेजबहार स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेस-1 में बारिश के बाद जलभराव की समस्या ने रहवासियों की परेशानी बढ़ा दी है। कॉलोनी के कई हिस्सों में गंदा पानी जमा होने से लोगों को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नालियों की नियमित सफाई नहीं होने और समुचित जल निकासी व्यवस्था के अभाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

रहवासियों के अनुसार बारिश के बाद कॉलोनी की सड़कों और आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा हो गया है। कई स्थानों पर गंदा पानी लंबे समय तक रुका हुआ है। इससे पैदल चलने के साथ-साथ दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित



हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नालियों में गंदगी और कचरा जमा होने के कारण पानी का बहाव बाधित हो रहा है। बारिश का पानी नालियों के जरिए बाहर निकलने के बजाय कॉलोनी के भीतर ही जमा हो रहा है।

लंबे समय तक गंदा पानी जमा रहने से कॉलोनी में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। रहवासियों ने आशंका जताई है कि जलभराव की स्थिति बनी रही तो मच्छरजनित और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लोगों ने सफाई के

साथ-साथ जमा पानी पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

कॉलोनीवासियों का आरोप है कि जलभराव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन इसके

स्थायी समाधान की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों ने हाउसिंग बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारियों से मौके का निरीक्षण कराने और नालियों की तत्काल सफाई कराने की मांग की है। रहवासियों का कहना है कि केवल जमा पानी हटाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। इसके लिए नालियों की नियमित सफाई के साथ बेहतर जल निकासी व्यवस्था विकसित करना जरूरी है। कॉलोनीवासियों ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर समस्या और गंभीर होने की आशंका जताई है।

बिजली के निजीकरण को लेकर कांग्रेस फैला रही भ्रम : मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली के निजीकरण को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की बिजली के निजीकरण की कोई मंशा नहीं है, और इस संबंध में जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है।

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिस सुनवाई को बिजली के निजीकरण से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है, वह एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसी रूटीन प्रक्रिया का अर्थ यह कतई नहीं है कि सरकार बिजली का निजीकरण करने जा रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस हमेशा की तरह इस विषय में भी लुपुथचार कर जनता को गुमराह करने और गलतफहमी पैदा करने का प्रयास कर रही है। प्रदेशवासियों को ऐसे



भ्रामक प्रचार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ बिजली वितरण में निजी भागीदारी पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि एक निजी कंपनी ने राजधानी में बिजली वितरण के लिए लाइसेंस मांगी है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार निजी कम्पनियों को लाइसेंस देकर बिजली में भारी वसूली उपभोक्ताओं से करने वाली है। कांग्रेस इसका हर मोर्चे पर विरोध करेगी।

काँकरोच जनता पार्टी की सियासी दस्तक

आदिति फडणीस

यह बात वर्ष १९८२ की है जब दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में युवा छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय शिक्षक दिलीप सिमियन कॉलेज के एक माली के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। सिमियन नक्सली आंदोलन से शुरुआत में ही जुड़े थे और सांप्रदायिक राजनीति के कट्टर विरोधी थे। मामला यह था कि कॉलेज प्रशासन ने बिना किसी जांच के उस माली का वेतन रोक दिया था। इस घटना के कुछ दिन बाद कॉलेज जाते समय कुछ लोगों के एक गिरोह ने सिमियन की पिटाई कर दी। सिमियन पर हमले के साथ एक युवा महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना से माहौल तनावपूर्ण हो गया था। कहा गया था कि महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डीयूएसयू) के कार्यालय में हुई। उस समय डीयूएसयू की कमान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीओपी) के पास थी। इस घटना ने कॉलेज परिसर की युवा महिलाओं को एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया। ये महिलाएं पहले से ही छेड़छाड़ जैसी घटनाओं से उरी-सहमी थीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों में गुस्सा और आक्रांश इतना बढ़ गया कि उन्होंने यह ठान लिया कि बस अब बहुत हो चुका। उन्होंने ‘कमेटी अगेंस्ट गुंडाइज्म’ (सीएजी) नाम से एक संगठन बनाया और रामजस कॉलेज के प्राचार्य करतार सिंह की मदद से परिसर की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कॉलेज परिसर सुरक्षित नहीं बनाए गए तो विश्वविद्यालय के कुलपति गुरुबख्श सिंह को भी पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। नतीजा यह हुआ कि करतार सिंह को छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया। उन्होंने निजी सुरक्षा कर्मियों की मदद से परिसर में दोबारा घुसने की कोशिश की। इस वजह से वह दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले ऐसे प्राचार्य के तौर पर ‘बदनाम’ हो गए जिन्हें शांति भंग करने और हिंसा के आरोप में निलंबित कर दिया गया। इस बीच, छात्रों ने रोजाना प्रदर्शन कर दिल्ली विश्वविद्यालय की सड़कें अवरूद्ध कर दीं। उन्होंने गुरुबख्श सिंह के कार्यालय की घेराबंदी कर दी। इस आंदोलन को और मजबूती इसलिए मिली क्योंकि इसकी अगुआई करने वाले छात्र कोई आम समूह नहीं थे बल्कि वे होनहार छात्र, मेधावी और और विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चे थे। इन छात्रों को सत्ता की राजनीति से कोई खास लगाव नहीं था। वे बस निष्पक्षता, न्याय और लोकतंत्र चाहते थे और यह भी चाहते थे कि संस्थान अपना काम ठीक से करें। भले ही उनके संगठन का कोई निश्चित ढांचा नहीं था मगर उनकी प्रेरणा सामूहिक सामाजिक चेतना को जगाने की एक कोशिश थी। जब सीएजी बन रहा था तब उसने अपनी पहचान तय करने में मुश्किल हो रही थी और वे कुछ सवालों से जूझ रहे थे। यानी हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं और जो जबरदस्त लाभबंदी हमने की है उसका क्या करें? इसके बाद लंबी बहस हुई कि आखिर हम हालात कैसे बदलें? राजनीतिक आंदोलनों में शामिल होकर या खुद एक राजनीतिक समूह बनकर? क्या हमें हमेशा अहिंसक रहने का संकल्प लेना चाहिए या राज्य के साधनों के खिलाफ किसी तरह की हिंसा जायज है? क्या सीएजी का अस्तित्व में बने रहना जरूरी था या मकसद पूरा होने के बाद (करतार सिंह के पद छोड़ने, परिसर में छात्राओं की जंदगी सुरक्षित होने का भरोसा मिलने के बाद) सबको वापस वहीं लौट जाना चाहिए था जहां वे पहले थे? ढांचा ज्यादा जरूरी है या विचार? बहरसें लंबी खिंची, लेकिन संगठन धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा। हालांकि इसके सदस्यों ने अपने अनुभव का इस्तेमाल अन्य जगहों पर किया।

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...) शिव शब्द शं मुखं नित्यतानन्दम् इ कारः पुरुषः स्मृतः। व कारः शक्तिरमृतं मेलनं शिव उच्यते।। (शिवपुराण विद्यश्चरी १२।७६) अर्थात्- श सुख एवं एकान्त आनन्द को कहते हैं।इ कार पर-मात्मा का बोधक है और व कार अमृत शक्ति का वाचक है, तीनों मुख जिसमें रहते हैं उसे शिव कहते हैं। गुरु शब्द गुणान् रुन्ध इति प्रोक्तो गुरुशब्दस्य विग्रहः। (शिवपुराण विद्या १८।१८२) अर्थात्-मुणों के आधायक को गुरु कहते हैं। विष्णु शब्द विष्ण्वति व्यापकत्वात् नम ख्यातं भविष्यति। (शिवपुराण रुद्र संहिता ६।४३) अर्थात् - व्यापक होने के कारण भगवान् का नाम	विष्णु ऐसा प्रसिद्ध होगा। इसीप्रकार अन्याय शब्दों के भी पुराण ग्रन्थों में निर्वचन प्राप्त होते हैं जो विस्तारभयात् यहाँ अङ्कित नहीं किये जा सकते। आयुर्वेद स्वास्थ्यरक्षा आयुर्वेद पर ही निर्भर है। लोग विदेशी दवाओं का सेवन करके धन धर्म तथा स्वास्थ्य तीनों चीजों को खो रहे हैं, परन्तु अपने आयुर्वेद की ओर ध्यान नहीं देते, परमात्मा ही उन्हें सुधार सकता। प्राचीन ऋषियों का तो सिद्धान्त है कि- यस्य देशस्य यो जन्तुस्तज्ञ जत्स्यौषधं हितम्।। अर्थात्- जो प्राणी जहां उत्पन्न होता है उसके लिए उसी देश की औषधियें हितकर हो सकती हैं। परन्तु आज स्वास्थ्य खराब हिन्दुस्तान नियों का हो और बोटलें खाली की जाएँ, इङ्ग्लैण्ड की और फ्रांस की ! यह अन्ध परम्परा अत्यन्त अनुचित है। क्रमशः ...
--	--



मोदी-जिनपिंग की मुलाकात से कुछ बात बनने की आस

हरि वर्मा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (१२-१३ सितंबर) और शंघाई शिखर सम्मेलन (एससीओ ३१ अगस्त १ सितंबर) से ऐन पहले भारत और चीन के बीच आपसी धींगामुश्ती हद तक नरम पड़ी है। आपसी तनातनी और वैश्विक हालात के बीच दोनों के लिए यह नरमी शुभ संकेत है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जिनपिंग भारत आने वाले हैं। ब्रिक्स के बहाने नरेंद्र मोदी और जिनपिंग में द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। इससे पहले शंघाई शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों की मुलाकात लगभग तय है। मोदी-जिनपिंग की इन मुलाकातों से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन जाकर वहां के विदेश मंत्री वांग यी से सीमा विवाद को लेकर उपजे ताजा हालात को शांत और स्थिर करने की दिशा में बड़ी पहल की है। अरुणाचल के नक्शे को लेकर वाकयुद्ध के बीच एनएसए डोभाल और वांग की मुलाकात में सीमा निर्धारण पर परामर्श तंत्र, दो हॉटलाइन चैनल, सैन्य और कूटनीतिक कोशिशों, सीमा सामान, पर्यावरण व अन्य क्षेत्रों में सहयोग के अलावा बहमपुत्र-सतलुज नदी पर हाइड्रोलॉजिकल (जल विज्ञान) डाटा साझा करने जैसे ८ अहम मुद्दों पर आपसी सहमति बनी है। नेपाल के ताजा जलप्रलय को देखते हुए बहमपुत्र-सतलुज नदी पर जल विज्ञान डाटा साझा करने पर राजमंदी दोनों के लिए हितकारी है। वैसे, हाईड्रोलॉजिकल डाटा साझा करने की पहल आज से करीब २० वर्ष पहले २००६ में ही हो गई थी। इस दिशा में फिर से बड़े एहतिर्याति कदम से हमारे हित और मजबूत व सुरक्षित होंगे। अभी तबाही झेल रहे नेपाल का यही आरोप है कि चीन ने समय से तिब्बत से होने वाली तबाही को लेकर उसे आगाह नहीं किया। ऐसे में नेपाल का मंजर सामने है। डोभाल-वांग की मुलाकात में यह भी तय हुआ कि सीमा विवाद पर अगले दौर की (२६ वीं) बातचीत अगले साल यानी २०२७ में भारत में हो होगी। यह भी सीमा विवाद हल की दिशा में भविष्य	क रोडमैप तैयार करता है। यूं तो भारत और चीन के बीच तनातनी अरसे से चली आ रही है। १९६२ के युद्ध के बाद सिक्किम के नाथुला-चोला में १९६७ में, अरुणाचल के तुलुंगला में १९७५ में, जून २०२० में पूर्वी लद्दाख के गलवान में, २०२२ में अरुणाचल के तवांग में टकराव हुए। २०२० के गलवान संघर्ष में तो हमारे २० जवान बलिदान तक हो गए। अब ताजा तनातनी अरुणाचल के नक्शे पर २७ स्थानों को लेकर उपजी है। अरुणाचल भारत का हिस्सा है और नक्शे पर २७ स्थान तय किए तो चीन को मिर्ची लगी। चीन हमेशा ही विस्तारवादी रवैया अपनाता रहा है जिसका भारत ने सदैव विरोध किया है। ऐसे में डोभाल-वांग की मुलाकात से सीमा विवाद को लेकर फिर से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के दरवाजे खोलने की पहल निश्चित तौर पर सराहनीय है। दोनों पहले की शांति व सुरक्षा की स्थिति पर राजी भी है। ऐसे में अब ब्रिक्स और शंघाई के बहाने मोदी-जिनपिंग की बातचीत के नये दरवाजे खुलने की संभावना बनी है। शंघाई शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जरिये से यह पखवाड़ा बेहद अहम साबित होने वाला है। दरअसल, विस्तारवादी चीन और विकासवादी भारत दोनों के लिए ताजा वैश्विक हालात के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मंच पर
---	---

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक का २५ अगस्त से लगभग १० सितंबर २०२६ तक,१७ दिवसीय तीन देशों अमेरिका,कनाडा और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा का २५ अगस्त से शुरू अमेरिका दौरा केवल एक संगठन के शताब्दी वर्ष का वैश्विक संपर्क अभियान नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत की विचारधारा,हिंदुत्व,धार्मिक स्वतंत्रता अल्पसंख्यक अधिकारों और भारतीय प्रवासी राजनीति को लेकर अमेरिका में चल रही पुरानी बहस का नया अध्याय बन गया है। २५ अगस्त २०२६ से शुरू हुए आरएसएस प्रमुख के अमेरिका-कनाडा-ब्रिटेन दौरे का उद्देश्य आरएसएस के अनुसार संगठन के १०० वर्ष पूरे होने के अवसर पर वैश्विक हिंदू और भारतीय समुदायों से संवाद करना तथा आरएसएस और भारत के बारे में मौजूद गलत धारणाओं को दूर करना है। लेकिन न्यूयॉर्क पहुंचते ही यह दौरा समर्थन और विरोध, दोनों का केंद्र बन गया। मैं मीडिया में आई रखबरो के हवाले से बताना चाहूंगा कि २९ अगस्त को प्रस्तावित यूनिवर्सल ऑननेस सेलिब्रेशन में आरएसएस प्रमुख के संबोधन को लेकर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी,पूर्व एनवायसी कम्पटीलर और कांग्रेस उम्मीदवार ब्रैंड लैंडर, कई इंटरफेथ एवं मानवाधिकार समूहों तथा यूएस सआईआरएफ ने गंभीर आपत्तियां उठाई हैं।दूसरी तरफ,अमेरिकी हिंदू संगठनों ने इसे हिंदू समुदाय की वैश्विक आवाज और वसुधैव कुटुम्बकम् के संदेश का मंच बताया हैआयोजकों का कहना है कि २०० से अधिक हिंदू-अमेरिकी संगठन इस आयोजन से जुड़े हैं।इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आरएसएस को लेकर अमेरिका में आपत्ति केवल आरएसएस प्रमुख के व्यक्तिगत बयानों तक सीमित नहीं है।आलोचकों की मुख्य आपत्ति आरएसएस की हिंदुत्व संबंधी वैचारिक भूमिका को लेकर है। आरएसएस स्वयं हिंदुत्व को भारतीय सभ्यता,सांस्कृतिक राष्ट्रवाद,सामाजिक संगठन और राष्ट्रीय एकता की अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करता है।आरएसएस की अपनी सामग्री में भागवत हिंदुत्व को सत्य, प्रेम और अपनत्व से जोड़ते हैं तथा संगठन सामाजिक समरसता, जातिगत भेदभाव के विरोध और सेवा को अपनी प्राथमिकताओं में बताता है। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि व्यवहार में हिंदुत्व की राजनीतिक व्याख्या बहुसंख्यकवादी



राजनीति को मजबूत कर सकती है और इससे मुस्लिम,ईसाई,सिख तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार प्रभावित होने का खतरा पैदा होता है।यही वह वैचारिक अंतर है जहां आरएसएस की आत्म-व्याख्या और उसके आलोचकों की व्याख्या एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है।यह लेख २८ अगस्त २०२६ तक उपलब्ध जानकारी पर मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है।

साथियों, न्यूयॉर्क में विरोध का सबसे प्रमुख राजनीतिक चेहरा मेयर जोहरान ममदानी बने हैं।एक अमेरिकी समाचार एजेंसी के अनुसार ममदानी ने आरएसएस प्रमुखके कार्यक्रम का सार्वजनिक रूप से विरोध किया और आरएसएस की विचारधारा को भारत के बहुलतावादी तथा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के विपरीत बताया। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी निजी कार्यक्रम को केवल राजनीतिक असहमति के आधार पर नगर प्रशासन द्वारा रोक देना अलग कानूनी प्रश्न है।रिपोर्टों के अनुसार ममदानी ने विरोध तो जताया है, लेकिन शहर के पास कार्यक्रम को रोकने की सीधी कानूनी शक्ति होने का प्रश्न अलग है।इसीलिए यह मामला केवल विचारधारा का नहीं, बल्कि अमेरिका मेंअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का भी बन गया है।ब्रैंड लैंडर और कई इंटरफेथ समूहों का विरोध भी इसी वैचारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है। नों रूम फॉर भागवत जैसे विरोध अभियान में मानवाधिकार, धार्मिकस्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है।विरोध करने वालों में हिंदूस फॉर ह्यूमन राइट्स,ईंडियन अमेरिकन मुस्लिम कौंसिल, इंटरफेथ सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क और अन्य समूहों के नाम सामने आए हैं। उनका तर्क है कि किसी व्यक्ति के हिंदू होने या हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के कारण विरोध नहीं किया जा रहा,बल्कि आरएसएस की राजनीतिक-सामाजिक भूमिका और उससे जुड़े

दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत



हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह सत्ता में आए। दोनों ही राष्ट्रवाद को उग्र भावना को भड़काकर सत्ता में आए थे। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था, इस वजह से इटली में असंतोष की भावना थी। जर्मनी में हिटलर भी इसी तरह कुछ कर रहा था।

एक दूसरी वजह, साम्राज्यवाद की भावना को भी माना जाता है ७ १९३१ में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया और तैयार हो चुका शुरू किया।

कथित अल्पसंख्यक-विरोधी प्रभावों के कारण आपर्ति है। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का कहना है कि आरएसएस को हिंदू समाज के सांस्कृतिक और सेवा संगठन के रूप में देखने के बजाय केवल राजनीतिक विवादों के चरम से देखना सटीकता से अनुचित है।

साथियों इसी विवाद को सबसे गंभीर रूप तब मिला जब यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ ने आरएसएस के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों की मांग कर दी। यह बताना जरूरी है कि इसकी वार्षिक रिपोर्ट मुख्यतः देशों को विशेष चिंता वाले देश (सीपीसी) और विशेष निगरानी सूची जैसी श्रेणियों में रखने की सिफारिश करती है।हालांकि २०२५ की उसकी रिपोर्टों में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई है और भारत को विशेष चिंता वाले देश की श्रेणी में रखने की सिफारिश की गई है/या भारत पर अलग गंभीर देश-अध्याय जारी किया गया है। इन निष्कर्षों को भारत सरकार ने पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज किया है।२६ अगस्त के अपने आधिकारिक बयान में यूएस सीआईआरएफ ने कहा कि उसे भागवत की अमेरिका यात्रा को लेकरगंभीर चिंता है।आयोग के चेयरमैन आसिफ महमूद ने अमेरिकी सरकार से आरएसएस के उन सदस्यों और भारतीय अधिकारियों पर लक्षित प्रतिबंधों पर विचार करने की अपील की जिन्हें वह धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन से जोड़ता है। आयोग ने विशेष रूप से मोहन भागवत का जारी वीजा रद्द करने और भविष्य में उनके अमेरिका प्रवेश को रोकने पर विचार करने की मांग की।यह ध्यान रखना जरूरी है कि यूएससीआईआरएफ एक अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी सलाहकारी आयोग है; उसकी सिफारिश अपने आप में अमेरिकी सरकार का वीजा रद्द करने का आदेश नहीं है। अमेरिकी एजेंसी ने भी स्पष्ट किया है कि आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं और अमेरिकी सरकार ने इन सिफारिशों पर कोई कार्रवाई घोषित नहीं की है।

साथियों, भारत के विदेश मंत्रालय ने यूएस सीआईआरएफ को पहले ही बिगड़ यानी पक्षपाती संस्था बताते हुए उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने २१ अगस्त २०२६ को कहा कि यह संस्था लंबे समय से भारत के बारे में डिस्पैराजिंग एंड

इन्फेलामेटरी टिप्पणियां करती रही है और उसके अपने एजेंडे हैं,इसलिए भारत को ऐसी संस्था से दूरी रखनी चाहिए। इस प्रकार एक ओर अमेरिकी आयोग भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर दबाव बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर भारत सरकार आयोग की पद्धति और निष्पक्षता पर ही सवाल खड़ा कर रही है।दिलचस्प बात यह है कि २०२६ का विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ।इसका एक स्पष्ट इतिहास २०१८ के शिकागो तक जाता है।सितंबर २०१८ में मोहन भागवत वर्ल्ड हिन्दू कांग्रेस में शामिल होने के लिए शिकागो पहुंचे थे। उस समय लगभग २,५०० प्रतिनिधि ६० देशों से सम्मेलन में आए थे। आयोजन का उद्देश्य वैश्विक हिंदू समुदाय को एक मंच पर लाना और हिंदू समाज से जुड़े सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करना था। लेकिन कार्यक्रम के बाहर और भीतर विरोध भी हुआ। साथियों, २०१८ में छिकागो साउथ एशिय्स फॉर जस्टिस से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने वर्ल्ड हिन्दू कांग्रेस में घुसकर स्टॉप हिन्दू फसकीज्म और आरएसएस टर्न अराउंड , वुर्ड डू नॉट वांट यू इन टाउन जैसे नारे लगाए। दो प्रदर्शनकारियों को डिसऑर्डरली कंडक्ट और ट्रेसपासिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे भारतीय सरकार की अल्पसंख्यकों से जुड़ी नीतियों का विरोध कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित हैं।उसी समय सिख कोऑर्डिनेशन कामिटी ईस्ट कोस्ट ने भी भागवत और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विरोध की तैयारी की थी और उन पर हिंदुत्व को बढ़ावा देने तथा सिख पहचान को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। साथियों, इसलिए २०१८ और २०२६ के बीच सबसे बड़ी समानता यही है कि दोनों बार विरोध का केंद्र हिंदू धर्म नहीं, बल्कि आरएसएस और हिंदुत्व की राजनीतिक- सामाजिक व्याख्या बनी। २०१८ में प्रदर्शनकारियों ने आरएसएस को हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ा और अल्पसंख्यक अधिकारों की चिंता जताई; २०२६ में वही बहस न्यूयॉर्क की राजनीति,इंटरफेथ संगठनों और यूएससीआईआरएफ के स्तर तक पहुंच गई है।अंतर यह है कि २०१८ में विरोध मुख्यतः सम्मेलन और प्रदर्शन के स्तर पर था, जबकि २०२६ में विवाद अमेरिकी राजनीतिक प्रतिष्ठान और धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी सरकारी सलाहकारी तंत्र तक पहुंच गया है।

दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत

१९३५ में इटली ने इथोपिया पर और १९३८ में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर अपनी साम्राज्यवादी नीतियों का प्रदर्शन किया था।

इस तरह जर्मनी, इटली और जापान तीनों का एक गुट बन गया, जिसे धुरी राष्ट्र के नाम से जाना गया। दूसरी तरफ फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और सोवियत संघ का अलग गुट बना, जिसे मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया।

धीरे-धीरे इस युद्ध का दायरा फैलता गया और ६० से भी ज्यादा देश इसमें शामिल हो गए।६ साल तक ये युद्ध चलता रहा। मरने वालों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस युद्ध में ७ करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। ६ साल बाद जापान पर परमाणु हमले के बाद इस युद्ध का अंत हुआ। ये इतिहास का सबसे

विनाशकारी युद्ध साबित हुआ।

६५ साल पहले बनी एलआईसी

भारत में पहली बीमा कंपनी साल १८१८ में स्थापित हुई। इसका नाम था- ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कलकत्ता। उस समय ये कंपनी भारतीयों का बीमा नहीं करती थी। बाद में इस कंपनी ने भारतीयों का बीमा करने की शुरुआत की, लेकिन भारतीयों से ज्यादा प्रीमियम रेट वसूला जाता था। १८७० में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसायटी की स्थापना हुई।

स्वदेशी आंदोलन के बाद देश में इंश्योरेंस कंपनियों की संख्या बढ़ती गई। १९३८ तक भारत में १७६ बीमा कंपनियां थीं जिनका सालाना कारोबार करीब ३०० करोड़ रुपए का था। धीरे-धीरे इन कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की मांग बढ़ने लगी।

आज का इतिहास

१५११	पीसा कार्डसिल खुला।
१८०७	अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति आरोन बर्ं राजद्रोह के मामले में निर्दोष पाये गये।
१८७८	एम्मा एम नट्ट अमेरिका में पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर बनीं।
१९२३	ग्रेट कैंटो भूकंप ने जापान के टोक्यो और योकोहामा में भयंकर तबाही मचायी।
१९३९	जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई।
१९४७	भारतीय मानक समय को अपनाया गया।
१९५६	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की स्थापना हुई।
१९५६	रज्यों के पुनर्गठन के लिए दोनों के बीच कमांडर स्तर का वार्ता के लिए प्वाइंट तय किए गए हैं। सीमा व्यापार के दरवाजे खोले जा रहे हैं। वैश्विक हालात के बीच आर्थिक चुनौतियों से उबरने की दिशा में यह दोनों के लिए ही लाभकारी है।
१९५७	सितंबर २०१४ में पहली बार मोदी-जिनपिंग गुजरात में मिले। फिर २०१९ में मोदी-जिनपिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मिले। अब करीब ७ साल बाद फिर से मोदी-जिनपिंग शंघाई और ब्रिक्स के बहाने मिलने वाले हैं। कूटनीतिक लिहाज से ये मुलाकात मायने रखेगी लेकिन सामरिक लिहाज से हमें चौकन्ना भी रहने की जरूरत है क्योंकि २०१४ की मुलाकात के बाद २०१६ में दोकलम में दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे के आमने-सामने आ गईं।
२०१९	को मुलाकात के बाद २०२० में गलवान संघर्ष हुआ। ऐसे में विस्तारवादी चीन से चौकन्ना रहते हुए कूटनीतिक मार्ग के जरिये विकास की राह पर अग्रसर होने की पहल निश्चित तौर पर सराहनीय है। ऐसे में उम्मीदी का ज सक्ती है कि इन मुलाकातों के बहाने अब आगे कुछ बात बन जाए क्योंकि वैश्विक हालात भी बुद्ध का मार्ग ही प्रशस्त करते हैं।

मनुरस्मृति में नारी को लेकर ऐसा लिखा क्या है? जिस पर होता है बवाल

अभिनय आकाश

हजार साल पुराना है उनका गुस्सा, हजारों साल पुरानी है उनकी नफरत

गोरख पांडे के इन शब्दों को अगर आज के समाज की असंलियत कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। सोचिए एक किताब जिसे कुछ लोग धर्म की बुनियाद मानते हैं और वहीं कुछ लोग उसे सरेंआम जलाकर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के सबसे असरदार और शायद सबसे विवादित ग्रंथ की मनुस्मृति की। आप में से कितने लोगों ने मनुस्मृति को पढ़ा है? आप में से बहुत सारे लोगों ने गीता को पढ़ा होगा। रामचरितमानस को पढ़ा होगा, महाभारत को पढ़ा होगा। कुछ लोगों ने प्राचीन पुस्तकों को जो अलग-अलग पुस्तकें हैं उन्हें पढ़ा होगा। वेदों को पढ़ा होगा और इनसे अपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। ऐसी ही एक प्राचीन पुस्तक है जिसे हम कहते हैं मनुस्मृति। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मनुस्मृति को अपना निशाना बनाया है। पुणे में छात्रों की गूंज नाम के अपने कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों से बात की थी और इस दौरान राहुल गांधी ने मनुस्मृति में एक श्लोक का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे यह किताब महिलाओं की आजादी के खिलाफ है और इस पर हमें शर्म आनी चाहिए। ऐसा राहुल गांधी ने कहा। अब सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी बार-बार मनुस्मृति को ही

अपना निशाना क्यों बनाते हैं? इस किताब का पूरा नाम मानव धर्म शास्त्र है। तो आज सबसे पहले आपको मनुस्मृति के बारे में बताते हैं। जब हम भारत में धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो अमूमन शुरुआत में दो प्रकार के ग्रंथ देखने को मिलते हैं। एक जिनको हम श्रुति ग्रंथ कहते हैं जिनको सुना गया समझा गया। एक उनको स्मृति ग्रंथ जिनको सुनने के बाद याद किया गया और फिर उसे लिखा गया। कई बार इनको उनके डिसाइपल्स द्वारा लिखा गया। तो श्रुति के बाद स्मृतियों का जो महत्व है। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म की अगर बात करें तो प्राचीन में बहुत सारे ग्रंथ जो थे वो इन्हीं विधियों से होकर आगे बढ़े हैं। वेदों की बात करें या अरण्यकों की बात करें। ब्राह्मस्य की बात करें या उन स्मृतियों की बात करें जिनमें से एक मनुस्मृति है। स्मृतियों की बात करें तो कुल लगभग 18 स्मृति है। अगर हम धर्मशास्त्र की बात करें तो 18 स्मृति है। जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, पराशर स्मृति, विष्णु स्मृति और बहुत सारी। इनमें से पहली स्मृति मनुस्मृति को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्मा थे उन्होंने मनु को ज्ञान दिया। ठीक है? मनु ने यही ज्ञान अपने शिष्य भृगु को दिया और भृगु ने अपने इस ज्ञान को आगे मानवता तक बढ़ाया। शुरुआत में ज्ञान की परंपरा को ऐसे बताया गया है।

इस किताब में 12 अध्याय हैं और लगभग



2694 श्लोक इस किताब में हैं। हिंदुओं की ऐसी मान्यताएं है कि इस पुस्तक को सृष्टि के पहले ईंसान ने लिखा था और उन्होंने ही इसके जरिए मानवता को तमाम तरह के कानून दिए। मतलब जो सृष्टि में पहला मनुष्य है उसने इसे लिखा। इसीलिए इसे मनुस्मृति कहा जाता है। यहां मनु का मतलब है पहला मनुष्य। हालांकि कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह पुस्तक आज से लगभग 2000 वर्ष पहले यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर के आसपास लिखी गई है और 200 ईसा पूर्व से 200 ईसवी के बीच इसे लिखा गया है। इस ग्रंथ में मनु ने जीवन दर्शन, प्रशासन, समाज की रचना, नीतियां और कानून के बारे में विस्तार से बताया है। यानी समाज को कैसे चलाना है। राजा से लेकर प्रजा तक सबका धर्म क्या होना चाहिए? आचार विचार क्या होना चाहिए? व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये सारी बातें इस पुस्तक में बताई गईं

है। यह जीवन जीने की एक पूरी पद्धति है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय यह पुस्तक लिखी गई तब तक ना तो बाइबल लिखी गई थी और ना ही कुरान लिखी गई थी। शासन और प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था में इस पुस्तक का इस्तेमाल ना सिर्फ भारत में बल्कि कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी हुआ जहां पर हिंदू साम्राज्य हुआ करते थे। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने हिंदू कोड बनाने में इस ग्रंथ का काफी इस्तेमाल किया था। लेकिन आजाद भारत के कानून में हमारे संविधान में इस पुस्तक की कोई जगह नहीं है।

यत्र नार्यस्तु पूजयते रमते तत्र देवता। हिंदी में इसका मतलब है जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह पुस्तक आज से लगभग 2000 वर्ष पहले लिखी गई थी। इसे आज की नैतिकता से जज नहीं किया जा सकता। बाइबल दास प्रथा को, स्लेवरी को समर्थन देती है। और कई जानकारों का दावा है कि कुरान में भी कई ऐसी बातें हैं जो महिला विरोधी हैं और इस पर आज भी बहस होती रहती है। यह एक विवाद का विषय है। जबकि ये दोनों ही पुस्तकें मनुस्मृति के कई 100 वर्ष

बाद लिखी गई थी। यह किताब दहेज के भी खिलाफ है। और तो और इसमें यह भी कहा गया है कि शूद्रों और महिलाओं को भी धर्म के रास्ते पर चलने का पूरा हक है।

2026 के एक फैसले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक विधवा के गुजारे भते के अधिकार को सही ठहराने के लिए मनुस्मृति का ही हवाला दिया था। ये दिखाता है कि ये महज इतिहास के पन्नों में दबी हुई कोई किताब नहीं है। और ये कोई एक आध बार नहीं हुआ है। 2019 से पहले ही सुप्रीम कोर्ट सात से भी ज्यादा बार अपने फैसलों में मनुस्मृति का जिक्र कर चुका था। अगर हाई कोर्ट्स की बात करें तो वहां तो इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा होता रहा है।

25 दिसंबर, 1927 का दिन था जब डॉ. अंबेडकर ने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया। अंबेडकर ने पहले से घोषणा कर दी थी कि वह इस हिंदू ग्रंथ को जलाएंगे। जो जगह उन्होंने इसके लिए चुनी वो महाड़ नाम का महाराष्ट्र का तटीय इलाका था, जो कोलाबा (अब रायगढ़) जिले में था। अंबेडकर मनुस्मृति को जातिवादी और पितृसत्तात्मक मानदंडों के खिलाफ मानते थे। बर्कौल उनके, मनुस्मृति ऐसा हिंदू ग्रंथ है, जो जाति उत्प्रीडन को संस्थागत बनाता था। निचली जातियों, विशेषकर दलितों और महिलाओं के शोषण और भेदभाव को उचित ठहराता था। डॉक्टर

अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर इसका विरोध किया था उन्हीं ने बाद में हिंदू कोड बिल की बहस में महिलाओं को प्रॉपटी में हक दिलाने के लिए मनुस्मृति के ही कुछ प्रोग्रेसिव श्लोकों का इस्तेमाल किया।

डॉ. बी आर आंबेडकर ने यह तर्क दिया था कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की बात ऋषि मनु जैसे स्मृतिकारों द्वारा कही गई थी। 24 फरवरी 1949 को संविधान सभा की बहस के दौरान उन्होंने कहा था-इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन दो स्मृतिकारों का मैंने उल्लेख किया है—याज्ञवल्क्य और मनु—वे उन 137 स्मृतिकारों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं जिन्होंने स्मृतियों की रचना करने का प्रयास किया था। इन दोनों ने ही यह व्यवस्था दी है कि पुत्री एक-चौथाई हिस्से की हकदार है। यह अत्यंत खेदजनक है कि किसी न किसी कारणवश कुरीतियों और प्रथाओं ने इस मूल विधान के प्रभाव को नष्ट कर दिया; अन्यथा हमारी अपनी स्मृतियों के आधार पर भी पुत्री एक-चौथाई हिस्सा पाने की पूरी हकदार होती। उन्होंने आगे कानूनों की तुलना में रीति-रिवाजों और प्रथाओं को प्राथमिकता देने के लिए प्रिवी काउंसिल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा न हुआ होता, तो मनुस्मृति ने वर्षों पहले ही महिलाओं और संपत्ति में उनके उत्तराधिकार के अधिकारों को सशक्त बना दिया होता।

हिंदू राष्ट्र का मतलब, मुसलमानों के बिना नहीं

सनत जैन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने शनिवार को वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जो कहा है, उसकी विश्व भर में चर्चा हो रही है। विशेष रूप से भारत में उनके बयान पर बड़ी प्रतिक्रियाएं देखे जा सकते हैं। मोहन भागवत ने न्यूयार्क में विचार व्यक्त करते हुए कहा, मानवता की एकता, भारत का पारंपरिक विचार है। हमारे नेताओं ने संविधान पर जोर दिया है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, भारत की राजनीति स्वार्थ आधारित हो गई है। जहां में और मेरा है वहां समाधान नहीं मिल रहा है। भागवत बोले सामाजिक धार्मिक संगठन राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करना चाहें, तो लोकतंत्र में जनमत से ही सरकार चलेती है। हमें मजबूत जनमत तैयार करना होगा, जो राजनीति को प्रभावित करे। उन्होंने कहा सारे रास्ते ईश्वर तक ले जाते हैं। मानव जीवन की अपनी गरिमा है। मनुष्य जीवन में किसी भी आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता है। जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उस समय कोई हिंदू यह नहीं सोचता है, कि भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए। पूरी मानवता एक है। विविधता हमारी आंतरिक एकता को मजबूत करती है। हमें उसको स्वीकार करते हुए सभी का सम्मान करना चाहिए। मोहन भागवत ने जो कहा है, उससे किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से भारत में मुसलमान और ईसाइयों को लेकर 80-20 का जो विवाद पैदा किया गया है, भारत में जिस तरह से धार्मिक एवं जाति समीकरण को दिशा में राजनीति बढ़ती चली जा रही है। मुसलमानों और ईसाइयों को एक विचारधारा के लोगों द्वारा तरह-तरह से प्रभावित किया जा रहा है। उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, वह दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रहें। खाना-पीना, शिक्षा और धार्मिक क्रियाकलाप हिंदुओं द्वारा तय किए जा रहे हैं। अन्य धर्म एवं जाति आधार उल्टा का पालन करने का दबाव सरकारी संरक्षण में बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अमेरिका में जो कहा है, वह अलग है भारत में जो हो रहा है, वह अलग है। मोहन भागवत के विदेश प्रवास के पहले ही अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा एवं

अन्य स्थानों पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। मोहन भागवत के वीजा को रद्द करने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने जैसी मांग अमेरिका में बड़ी तेजी के साथ उभरी है। जिसके कारण मोहन भागवत का यह दौरा विवादों से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख, समय-समय पर जो कहते हैं, उस पर वह ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रहते हैं। हाल ही में जब वह अमेरिका के दौर में गए वहां पर उनके उद्योगपतियों से भेंट के कार्यक्रम को गुप्त रखा गया। भारत में निवेश करने के लिए उद्योगपतियों को जो कठिनाइयां हो रही हैं उस पर उन्होंने चर्चा की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के स्वयंसेवक रह चुके हैं। भारत और सारी दुनिया के देशों में यह माना जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सलाह पर ही वर्तमान सरकार पिछले 12 वर्षों से काम कर रही है। ऐसी स्थिति में मोहन भागवत के इस बयान को अमेरिका में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। विश्व के कई देशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सैकड़ो अनुवांशिक संगठन है। जो अलग-अलग तरीके से अपनी बात करते हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, जिसके बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुवांशिक संगठन तरह-तरह से हस्तक्षेप करके संबंधित वर्ग को अपने पक्ष में लाने का प्रयास न करते हों। वह जो कहते हैं, वह करते नहीं है। कुल मिलाकर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर एक कट्टर संगठन के रूप में भारत और दुनिया के देशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान बनी है। विदेश में एक कट्टरवादी संगठन के रूप में संघ को पहचान मिली है। भारत में ईसाई और मुस्लिमो के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उसकी चर्चा पिछले एक दशक से दुनिया के देशों में हो रही है। इस छवि को मिटा पाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुवांशिक संगठनों के लिए बहुत आसान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार आयोग संगठन एवं अन्य धार्मिक संगठन यह मानकर चलते हैं, भारत में मानव अधिकारों का उल्लंघन अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रहा है। इसमें भारत सरकार की भी सहमति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की कथनी और करनी में बड़ा अंतर देखने को मिलता है।

प्रभु चावला

अरस्तू का मानना था कि गणतंत्र की शक्ति अंततः उसे चलाने वालों के चरित्र पर निर्भर करती है। मोटेस्क्वी ने चेतावनी दी थी कि यदि राजनीतिक शक्ति पर कोई नियंत्रण न रखा जाए, तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी निर्धारित सीमाओं से परे फैलने लगती है। जबकि एडमंड बर्क ने कहा कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि का कर्तव्य केवल अपनी जनता की इच्छाओं को आंख मूंदकर मानना नहीं है, बल्कि देशहित में अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करना भी है। बर्क के लगभग ढाई शताब्दी बाद, भारत का लोकतंत्र एक बिल्कुल अलग प्रश्न पर आ गया है।

जनता को अपने नाम पर सत्ता का प्रयोग करने वालों के लिए कितना भुगतान करना चाहिए? जॉन लॉक का मानना था कि सरकार का उद्देश्य सत्ता सौंपने वालों के अधिकारों की रक्षा करना है, जबकि बर्क प्रतिनिधि सरकार को निर्वाचित व्यक्ति और मतदाता के बीच एक गंभीर समझौते के रूप में देखते थे। दोनों में से किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि लोकतंत्र एक दिन किसी कॉर्पोरेट संस्था की तरह संस्थागत ढांचे में ढल जाएगा, जिसमें वेगन, भत्ते, वाहन, घर और विशेषाधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला होगी लेकिन यही वो असहज वास्तविकता है जिसका सामना भारत कर रहा है।

जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी। जोसेफ विजय ने घोषणा की कि राष्‍ट्र के सभी 234 विधायकों को सरकारी वाहन, ईंधन, रखरखाव और चालक खर्च के लिए प्रति माह 75,000 रुपए और सहायक के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे, तो उनका इरादा शायद विधायकों को अपने निर्वान क्षेत्र के लोगों की सेवा करने की क्षमता को मजबूत करना रहा होगा। पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए इस पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। इसके साथ ही, विजय ने अनजाने में प्रतिनिधि सरकार की कीमत और उससे भी महत्वपूर्ण, इस बात पर एक व्यापक बहस को फिर से शुरू कर दिया है कि क्या राजनीतिक पद की बढ़ती लागत लेन-देन वाली राजनीति का रूप ले रही है।

विधायकों को उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करना पूरी तरह से जायज है। एक विधायक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करे, जनसभाओं में भाग ले, अधिकारियों से मिले, योजनाओं का निरीक्षण करे और हजारों व्यक्तिगत शिकायतों का समाधान करे।



तमिलनाडु के कई विधायक पहली बार चुने गए हैं और उनके पास स्थापित राजनेताओं की तरह व्यक्तिगत संसाधन नहीं हो सकते हैं। लेकिन उचित सहायता और राजनीतिक उदारता के बीच एक ऐसी रेखा है जिसे लोकतांत्रिक सरकारें लगातार पर करती जा रही हैं। सार्वजनिक सेवा को सक्षम बनाने के लिए बनाई गई सुविधा आसानी से एक विशेषाधिकार बन सकती है, जो एक बार मिल जाने पर अधिकार का रूप ले लेती है। दूसरी ओर नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक खर्च को नियंत्रित करने, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और सरकारी विभागों में मितव्ययिता को स्वीकार करें। इस विरोधाभास का बचाव करना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। यह सिर्फ तमिलनाडु की ही बात नहीं है। बिहार इसका एक और उदाहरण है।

बिहार में सत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्था बेहद उदार रही है। राज्य चुनावों से ठीक पहले, इसने विधायकों के लिए अतिरिक्त सरकारी आवास और नए आवासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी दी। सरकारें बदलती हैं, पार्टियां बदलती हैं और राजनीतिक बयानबाजी भी बदलती है, लेकिन सत्ता मिलने के बाद, राजनीतिक वर्ग मानो एक साझा भाईचारे को फिर से खोज लेता है- विधानसभा में बैठे लोगों के लिए बेहतर गाड़ियां, बेहतर घर, बेहतर वेतन और बेहतर सुविधाएं। नागरिकों को लगातार वित्तीय समझदारी की याद दिलाई जाती है और विधायकों को, उससे भी कहीं अधिक बार, इस बात की याद दिलाई जाती है कि जनता के खजाने से क्या-क्या सुविधाएं मिल सकती हैं।

इसीलिए सवाल को इस बात तक सीमित नहीं किया जा सकता कि विधायकों या सांसदों को जरूरत से ज्यादा वेतन मिलता है या नहीं। उन्हें पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए। असली मुद्दा यह है कि सार्वजनिक पद से मिलने वाला

वेतन, उसे पाने वालों द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों से कितना मेल खाता है।

विर्डबना यह है कि राजनीतिक वर्ग अधिक खर्चीला हो गया है, जबकि विधायिका स्वयं कम विचार-विमर्श करने वाली हो गई है। राज्य विधानसभाएं औसतन वर्ष के केवल एक छोटे हिस्से में ही बैठक करती हैं और कई राज्यों में बैठकों के दिनों की संख्या बेहद कम रही है। संसद भी इस समस्या से अछूती नहीं रही है।

सत्रों में बार-बार स्थागन, विरोध प्रदर्शन, वॉकआउट और पक्षपातपूर्ण टकराव देखने को मिल रहे हैं, जिससे कानून, व्यव्य और कार्यकारी नियंत्रों की गहन समीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि लोकतंत्र की गुणवत्ता को केवल बैठकों की संख्या से मापा जा सकता है।

लेकिन जब विधायी समय कम होता जाता है और राजनीतिक विशेषाधिकार बढ़ते जाते हैं, तो नागरिक को यह सवाल पूछने का पूरा अधिकार है कि क्या ये दोनों प्रवृत्तियां अनिश्चित काल तक साथ-साथ चल सकती हैं। अनौपचारिक अनुमानों के अनुसार, सरकारी खजाना 4,200 से अधिक विधायकों और 788 सांसदों पर सालाना 2,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करता है।

इसके अलावा, उन्हें अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सुविधाओं पर खर्च करने के लिए एक करोड़ रुपए से पांच करोड़ रुपए तक की राशि भी दी जाती है। इस बात का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि प्रत्येक विधायक द्वारा किए गए इतने बड़े वित्तेकाशीन खर्च से हमारे गांव या छोटे कस्बे पहले से बेहतर हुए हैं। भारत को लोकतंत्र पर पैसा खर्च करना ही चाहिए। लेकिन लोकतंत्र का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि वह अपने शासकों के साथ कितनी उदारता से व्यवहार करता है। अंततः उसका मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि शासन करने वाले लोग उनके हाथों में सौंपे गए धन, संस्थाओं और विश्वास के साथ कितनी जिम्मेदारी से व्यवहार करते हैं।

एक परिपक्व लोकतंत्र को केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या वह अपने राजनेताओं का खर्च उठा सकता है; उसे समय-समय पर यह भी पूछना चाहिए कि क्या उसके राजनेताओं ने उस अत्यधिक कीमत को सही ठहराने लायक प्रदर्शन किया है, जो जनता उनके लिए चुका रही है। भारत का लोकतंत्र आज एक बिल्कुल अलग सवाल के सामने खड़ा है-क्या भारत को वेतन पाने वाला लोकतंत्र चाहिए या परफॉर्मंस देने वाला लोकतंत्र?

बदलते युद्ध के दौर में भारत की बढ़ती ताकत

कातिलाल मांडोट

बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल और युद्ध के तेजी से बदलते स्वरूप के बीच भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर आधुनिक हथियारों और स्वदेशी तकनीक का विस्तार भारतीय रक्षा व्यवस्था को नई ताकत दे रहा है। इसी क्रम में अमेरिकी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल प्रणाली की संभावित खरीद को भारत की सैन्य तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कंधे से दागी जाने वाली यह प्रणाली आधुनिक बख्तरबंद लक्ष्यों से निपटने की क्षमता बढ़ाने के साथ सैनिकों को युद्ध के मैदान में अधिक लचीलापन दे सकती है।

अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग पिछले कुछ वर्षों में लगातार गहरा हुआ है। जैवलिन प्रणाली को लेकर लंबे समय से चल रही बातचीत का आगे बढ़ना इसी बढ़ते रणनीतिक सहयोग का संकेत है। अमेरिकी कंपनियों लॉकहीड मार्टिन और रैथियॉन द्वारा विकसित जैवलिन को दुनिया की प्रमुख एंटी टैंक मिसाइल प्रणालियों में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता लक्ष्य को पहले से निर्धारित कर उसके बाद मिसाइल को स्वतः मार्गदर्शन के जरिए लक्ष्य तक पहुंचाने की क्षमता है। यही कारण है कि आधुनिक युद्ध में ऐसी प्रणालियां पैदल सैनिकों की क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाली मानी जाती हैं।

भारत के लिए इस सौदे का महत्व केवल किसी विदेशी हथियार की खरीद तक सीमित नहीं है। इसके पीछे व्यापक रणनीतिक सोच भी दिखाई देती है। भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान से जुड़ी दोहरी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक ओर पश्चिमी सीमा पर मैदानी और रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तरी सीमा पर अत्यधिक ऊंचाई वाले दुर्गम इलाके हैं। ऐसे में हल्की, मोबाइल और आधुनिक एंटी टैंक प्रणालियां सेना की परिचालन क्षमता को मजबूत कर सकती हैं।

जैवलिन के साथ भारत की रक्षा रणनीति का दूसरा



महत्वपूर्ण पहलू स्वदेशी उत्पादन है। भारत लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि भविष्य में अत्याधुनिक हथियारों के लिए विदेशी निर्भरता कम से कम हो। इसी सोच के तहत देश में एंटी टैंक मिसाइलों की स्वदेशी क्षमता विकसित की जा रही है। डीआरडीओ की स्वदेशी प्रणालियां इसी प्रयास का हिस्सा हैं। विदेशी तकनीक और घरेलू उत्पादन क्षमता का संयोजन आने वाले वर्षों में भारतीय रक्षा उद्योग को और मजबूत कर सकता है।

‘शेर’ के साथ आत्मनिर्भरता को नई शक्ति

भारतीय रक्षा आत्मनिर्भरता की तस्वीर केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं है। अमेठी के कोरवा स्थित कारखाने में तैयार की जा रही एके-203 अर्सेनल राइफल इसका बड़ा उदाहरण है। ‘शेर’ नाम से पहचानी जा रही यह राइफल भारतीय सैनिकों को आधुनिक व्यक्तिगत हथियार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत में इसके उत्पादन से न केवल सेना की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी, बल्कि देश में रक्षा विनिर्माण का आधार भी व्यापक होगा।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अर्थ अब केवल हथियार बनाना नहीं रह गया है। इसका मतलब डिजाइन, अनुसंधान, उत्पादन, परीक्षण, रखरखाव और तकनीकी उत्पन्न की पूरी व्यवस्था को देश के भीतर मजबूत करना है। भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। निजी क्षेत्र और सरकारी रक्षा

प्रतिष्ठानों की बढ़ती भागीदारी ने देश के रक्षा उद्योग को नई गति दी है।

युद्ध की तस्वीर बदली, सेना भी बदल रही

आज का युद्ध केवल टैंक, तोप और राइफल के सहारे नहीं लड़ा जाता। ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सटीक निशाना साधने वाली प्रणालियां, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और वास्तविक समय में मिलने वाली खुफिया जानकारी युद्ध की दिशा तय करने लगे हैं। भारतीय सेना भी इसी बदलते स्वरूप के अनुरूप अपनी क्षमताओं में बदलाव कर रही है।

हाल के वर्षों में सेना ने निगरानी और सटीक प्रहार करने वाली तकनीकों पर विशेष जोर दिया है। लंबे समय तक निगरानी रखने वाले ड्रोन, कामिकाजी ड्रोन, आधुनिक रॉकेट प्रणाली और अन्य मानवरहित तकनीकें सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन प्रणालियों की मदद से दुश्मन की गतिविधियों पर दूर से नजर रखने और जरूरत के समय सटीक कार्रवाई करने की क्षमता बढ़ती है।

ड्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया है। बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों और ड्रोन से निपटने के लिए नई पीढ़ी की वायु रक्षा और काउंटर-ड्रोन प्रणालियों पर जोर दिया जा रहा है। इससे युद्ध के मैदान में सैनिकों और महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

तोपों से लेकर लड़ाकू विमानों तक मजबूत होती शक्ति

भारत की सैन्य शक्ति का विस्तार केवल थल सेना तक सीमित नहीं है। स्वदेशी तोप प्रणालियां, आधुनिक रॉकेट सिस्टम और लंबी दूरी तक प्रभावी हथियार भारतीय सेना की मारक क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। वायुसेना में तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमान और राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान भारत की हवाई क्षमता को नई मजबूती देते हैं। अपाचे जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी जमीनी अभियानों में सेना को महत्वपूर्ण हवाई समर्थन उपलब्ध कराते हैं।

ताशकंद में मोदी: यूरेनियम की दीर्घकालिक

आपूर्ति व्यवस्था पर सहमति भी अहम

प्रधानमंत्री मोदी ऐसे समय में मध्य एशिया की अपनी चार दिवसीय यात्रा पर हैं, जब वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है और मध्य एशिया आर्थिक, सामरिक और ऊर्जा संबंधी हितों का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव से उनकी मुलाकात के साथ शुरू हुई यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अब इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को महज ऐतिहासिक व सांस्कृतिक निकटता तक सीमित रखने के बजाय व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और संपर्क के व्यापक रणनीतिक ढांचे में बदलना चाहता है। ऐसे में, इस यात्रा को भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ जैसी पहलों के समानांतर ‘एक्ट स्टेटल एशिया’ नजरिये को मजबूत करने के अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए। मध्य एशिया के संसाधनों तक विश्वसनीय और दीर्घकालिक पहुंच भारत की आर्थिक सुरक्षा का अहम हिस्सा बन सकती है। दूसरी तरफ, मध्य एशियाई देश भी चीन व रूस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती संपर्क की है, क्योंकि मध्य एशिया तक भारत की सीधी स्थलािय पहुंच नहीं है और पाकिस्तान के साथ ऐसे संबंध नहीं हैं कि उसके रास्ते व्यापारिक संपर्क पर निर्भर रहा जा सके। ऐसे में जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे जैसे विकल्पों को प्रभावी बनाया जाए। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह चौथी उज्बेकिस्तान यात्रा है और सत्ता में आने के एक वर्ष बाद वह मध्य एशिया में सबसे पहले उज्बेकिस्तान ही गए थे। रविवार को हुई इस वार्ता के बाद दोनों देशों द्वारा अपने संबंधों



को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने और यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक व्यवस्था बनाए जाने पर सहमति जताना महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि यूरेनियम आपूर्ति पर पिछले करीब दो महीने के भीतर यह दूसरी बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले जुलाई में अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक अहम समझौता किया था। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का दूसरा अहम पक्ष उज्बेकिस्तान के बाद किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में उनकी भागीदारी है, जो इस पूरे दौरे को व्यापक क्षेत्रीय महत्व देती है। ताशकंद यात्रा की अहमियत सिर्फ उज्बेकिस्तान के साथ संबंधों तक सीमित नहीं है। यह भारत की उस व्यापक विदेश नीति का हिस्सा है, जिसमें बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच नए साझेदारों, नए बाजारों और नए रणनीतिक विकल्पों की तलाश की जा रही है। इस दौरान होने वाली घोषणाएं अगर सही ढंग से जमीन पर उतरती हैं, तो ताशकंद से शुरू हुई पहल मध्य एशिया में भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक उपस्थिति की मजबूत नींव बन सकती है।

नवाखाई ऋषि पंचमी के अवसर पर स्थानीय अवकाश 15 सितंबर को

महासमुन्द्र। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विनय कुमार लंगेह ने सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुक्रमांक-चार के नियम-आठ के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलेण्डर वर्ष 2026 के लिए घोषित स्थानीय अवकाश की तिथि में संशोधन किया है। पूर्व में जारी आदेश में नवाखाई के अवसर पर 18 सितम्बर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। उक्त स्थानीय अवकाश की तिथि को परिवर्तित करते हुए अब नवाखाई (नुआखाई) ऋषि पंचमी के अवसर पर मंगलवार 15 सितम्बर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह स्थानीय अवकाश जिला महासमुन्द के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं के लिए लागू होगा। उक्त स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय एवं उप कोषालय के लिए लागू नहीं होगा।

वैज्ञानिक मत्स्य पालन से कामिनी की आय में हुआ इजाफा

एमसीबी। मेहनत, सही तकनीक और विभागीय मार्गदर्शन का साथ मिले तो सीमित संसाधनों से भी बेहतर आमदनी का रास्ता तैयार किया जा सकता है। इसकी प्रेरक मिसाल हैं खोंगापानी, विकासखंड मनेन्द्रगढ़ की मत्स्य कृषक कामिनी रोहतिया, जिन्होंने वर्ष 2022 में मत्स्य विभाग के सहयोग से अपने लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के तालाब में वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन शुरू किया। आज यही तालाब उनके लिए आय का महत्वपूर्ण साधन बन गया है और वे प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख रुपये का लाभ प्राप्त कर रही हैं। मत्स्य पालन शुरू करने से पहले कामिनी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थीं। कृषि कार्य में मेहनत अधिक होने के बावजूद अपेक्षाकृत कम आय प्राप्त होती थी। वर्ष 2022 में मत्स्य विभाग की तैनीन तालाब निर्माण योजना के अंतर्गत उन्हें लगभग 1 हेक्टेयर तालाब निर्माण का लाभ मिला। इसके बाद उन्होंने तालाब का बेहतर उपयोग करते हुए मत्स्य पालन को अपनी आजीविका का साधन बनाया।

विशालकाय पेड़ गिरने से लगी वाहनों की लंबी कतार

गरियाबंद। नेशनल हाइवे 130 सी एक बार फिर जाम हो गया है। जुगाड़ के पास सड़क पर विशालकाय पेड़ गिरने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। झारियाबहरा से ध्रुवगढ़ी के बीच नेशनल हाइवे का सिंगल वे है। ऐसे में हाइवे में इस 40 किमी में अक्सर सड़क जाम हो जाता है। अबकी बार भी ऐसा ही हुआ है, जब विशालकाय पेड़ के गिरने से सड़क के दोनों छोर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। वन अमले को इसकी सूचना देने के बाद धराशाई पेड़ को हटाने टीम भेजी गई है। बता दें कि हाइवे में इस तरह के बाधा आए दिन होते रहता है। बारिश भर होने वाले इस परेशानी से निपटने नेशनल हाइवे के पास कोई पुख्ता इंतजामात नहीं है।



20 किलो कॉपर वायर चोरी, पांच गिरफ्तार

अंबिकापुर। जिले में बैकुंठपुर के कंचनपुर स्थित कोविड अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट से करीब 80 हजार रुपए कीमत के कॉपर वायर चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। थाना बैकुंठपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए कॉपर वायर में से 20 किलो तार बरामद किया गया है। पुलिस अब शेष चोरी के माल की बरामदगी और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार 8 जनवरी की दरम्यानी रात अज्ञात चोर कंचनपुर स्थित कोविड अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में लगे कॉपर वायर चोरी कर ले गए थे। चोरी किए गए तार की अनुमानित कीमत करीब 80 हजार रुपए बताई गई है। शिकायत मिलने पर बैकुंठपुर थाने में अपराध क्रमांक 08/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय कर संदिग्धों की तलाश शुरू की। सूचना के आधार पर चरचा निवासी अर्जुन बसौर, विजय बसौर और संतोष कुमार चौधरी को हिरासत में लेकर पृछताछ की गई।

स्टाफ त्वाटर् में मिला डॉ. का शव; मिले चोट के निशान

कोरबा। कोरबा के ईएसआईसी अस्पताल परिसर स्थित स्टाफ क्वार्टर में 30 वर्षीय डॉक्टर एल्विन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सोमवार सुबह रोजाना की तरह इयूटी पर नहीं पहुंचने पर अस्पताल के कर्मचारी उनके क्वार्टर पहुंचे, जहां वह मृत अवस्था में मिले। पुलिस ने शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई है। हालांकि घटनास्थल की जांच के दौरान डॉक्टर के हाथ पर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस मामले पर जांच कर रही है। घटना का पता उस समय चला, जब डॉक्टर एल्विन सुबह अस्पताल की ओपीडी में इयूटी देने नहीं पहुंचे। काफी समय बीतने के बाद भी उनके नहीं आने पर अस्पताल के कर्मचारियों को चिंता हुई। कर्मचारी उनके स्टाफ क्वार्टर पहुंचे और दरवाजा खटखटाकर आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद कर्मचारी कमरे के भीतर पहुंचे तो डॉक्टर एल्विन मृत अवस्था में पड़े मिले। कर्मचारियों ने तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की।

भाई से झगड़े के बाद बिजली के टावर पर चढ़ा युवक

बिलासपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के दयालबंद में शनिवार को भाई से विवाद के बाद नाराज एक युवक बिजली के टावर पर चढ़ गया। युवक को ऊंचाई पर बैठा देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। करीब दो घंटे तक मोहल्लेवासी युवक को समझाकर नीचे उतरने के लिए मनाते रहे। आखिरकार मोहल्ले के दो युवकों ने बातचीत कर उसे भरोसे में लिया और सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसके बाद पुलिस युवक को थाने ले गई, जहां पूछताछ के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार दयालबंद स्थित दुर्गा मंदिर के पीछे रहने वाले कुंदन केसरी (32) पिता कमल केसरी का शनिवार को किसी बात को लेकर अपने भाई से विवाद हो गया था। विवाद के बाद वह काफी नाराज हो गया और घर से निकल गया। कुछ देर बाद कुंदन नदी किनारे गुरुनानक स्कूल के पास स्थित बिजली के टावर पर चढ़ गए। उसे टावर पर चढ़ा देखकर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

नीचे उफनती नदी, ऊपर उगमगाता बांस का पुल

कबीरधाम। जिले के पंडरिया विकासखंड में विकास के दावों के बीच जमीनी हकीकत सामने आई है। गोरखपुर खुर्द और उसलापुर गांव के बीच करंनाला नदी पर पक्का पुल नहीं होने से ग्रामीणों ने खुद चंदा जुटाकर बांस का अस्थायी पुल तैयार कर लिया है। करीब 15 फीट की ऊंचाई पर बना यह पुल अब ग्रामीणों की मजबूरी का रास्ता बन गया है। करंनाला नदी पर बने इस अस्थायी पुल के नीचे पानी का तेज बहाव और ऊपर डामगाता बांस का पुल, इसी जोखिम भरे रास्ते से रोज स्कूली बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और किसान नदी पार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल पर थोड़ी सी भी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। नीचे उफनती नदी के कारण किसी के संतुलन बिगड़ने पर सीधे पानी में गिरने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों के अनुसार यह रास्ता उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राशन और अन्य जरूरी सामान लाने से लेकर खेती-किसानी के काम तक के लिए उन्हें इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। स्कूली बच्चे भी रोज इसी पुल के जरिए स्कूल आते-जाते हैं।

तेज बहाव में फंसे दो युवक का लोगों ने बचाया

कोरबा। शनिवार को हुई तेज बारिश के बाद दादर नाला उफान पर आ गया। इसके बावजूद स्कॉर्पियो सवार दो युवकों ने बहते नाले को पार करने की कोशिश की। बीच नाले में पहुंचते ही तेज बहाव के कारण वाहन अनियंत्रित होकर बहने लगा और दोनों युवक उसमें फंस गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। काफी मशक़त के बाद स्कॉर्पियो को भी नाले से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम दादर नाले में जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने स्कॉर्पियो सवार युवकों को नाला पार नहीं करने की सलाह दी थी लेकिन उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और वाहन नाले में उतार दिया। बीच नाले में पहुंचते ही पानी का तेज बहाव आया और स्कॉर्पियो बहने लगी। देखते ही देखते वाहन का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया। अंदर फंसे दोनों युवकों ने मदद के लिए शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास के बाद दोनों को बाहर निकाला।

बिलासपुर हिंसा मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, दोनों पक्षों के 11 आरोपी

बिलासपुर। न्यायधानी

बिलासपुर में 28-29 अगस्त की दरमियानी रात हुए बवाल के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पथराव और तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस ने पहले दोनों पक्षों के 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ नामजद समेत अन्य आरोपियों पर सड्द्रकदर्ज की थी। इसके बाद पुलिस ने संदिग्धों की धरपकड़ शुरू करते हुए 16 लोगों को हिरासत में लिया और अब मामले में दोनों पक्षों के कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस के अनुसार, अपराध क्रमांक 488/2026 के तहत 8

न्यायधानी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी खपरगंज, तालापारा, जुनी लाइन और सरकंडा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें मौला बक्स उर्फ जुब्बू, शेख अजरुद्दीन उर्फ अज्जू, मोहम्मद जाहिद खान, सफीक अहमद उर्फ राजा खान, शकीर उर्फ सोनू, मोहम्मद लाईक, रेहान अली उर्फ ईरानी और मो. जुनैद शामिल हैं। वहीं, अपराध क्रमांक 489/2026 के तहत पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजू यादव उर्फ नान, राकेश यादव उर्फ रिकु क्रमांक 488/2026 के तहत 8



इनमें राजू यादव और राकेश यादव कुंदरापारा के रहने वाले हैं, जबकि छत्रपाल साहू डबरीपारा निवासी है। बवाल के दौरान तोड़फोड़ की भी

मुताबिक 8 वाहनों और एक दुकान को नुकसान पहुंचाया गया। इनमें 6 चार पहिया वाहन, एक ई-रिक्शा और बाइक शामिल हैं। पथराव के कारण एक मकान की छिड़कियों के

तीन चरणों में गिरता है मलांजकुडुम जलप्रपात

बारिश में बढ़ जाती है खूबसूरती, बस्तर के प्रवेश द्वार कांकेर का पर्यटन स्थल



साथ नीचे गिरता है, तो पूरा इलाका किसी प्राकृतिक चित्र की तरह नजर आता है। मलांजकुडुम जलप्रपात तीन तिनकों से मिलकर बना है। इसके अलग-अलग चरणों की ऊंचाई करीब 10 मीटर, 15 मीटर और 9 मीटर बताई जाती है। वहां स्थानीय स्तर पर इसके तीन चरणों को करीब 60 से 65 फीट, 40 से 45 फीट और 20 से 25 फीट की ऊंचाई से गिरे जाने जलप्रपात के रूप में बताया जाता है। यह जलप्रपात दूध नदी क्षेत्र में स्थित है। कांकेर जिला छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है

12 जुआरियों को रंगे हाथ दबोचा, 3 लाख रुपये व मोबाइल जब्त

दुर्ग। दुर्ग पुलिस ने भिलाई के एक मकान में चल रहे जुए के फंड पर दबिश देकर 12 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 लाख 16 हजार रुपये नकद और करीब 2 लाख रुपये कीमत के 12 मोबाइल फोन सहित ताश की पत्तियां जब्त की हैं। मामला भिलाई के छवनी थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 34 कैंप का है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि वार्ड 34 कैंप के एक मकान में अवैध रूप से जुआ संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम और एसीसीयू की टीम मौके पर पहुंची और मकान में दबिश दी। इस दौरान मौके पर 12 लोग जुआ खेलते हुए मिले, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 लाख 16 हजार रुपये की नकदी, ताश की पत्तियां और करीब 2 लाख रुपये कीमत के 12 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस के मुताबिक, जुआ खेलने में इस्तेमाल की जा रही सामग्री को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिबंध अधिनियम 2022 के तहत छवनी थाना



में अपराध दर्ज किया है। पुलिस कार्रवाई में महेंद्र कुमार सोनकर, कलीम खान, जी शिवा शंकर राव, आशीष ताम्रकार, श्रीधर्माजी, प्रेम प्रेमचंद, ऐन धन राजू, भगवत प्रसाद, सपन चंद्र डे, राजेंद्र कुमार कौशिक, दिनेश साओ और बलजिन्दर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इस कार्रवाई के बाद इलाके में अवैध जुआ गतिविधियों को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

कांच भी टूट गए थे। स्थिति को नियंत्रित करने के दौरान पुलिसकर्मी भी पथराव की चपेट में आए। घटना में तारबाहर थाना प्रभारी रविशंकर तिवारी समेत 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। टीआई के सिर में गंभीर चोट आने की जानकारी सामने आई है। घायल पुलिसकर्मियों का उपचार कराया गया। घटना के बाद खपरगंज, तेलीपारा रोड, मध्यनगरी चौक, सिम्स चौक और करोना चौक में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। स्थानीय पुलिस बल के अलावा दूसरे जिलों से करीब 350 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को बुलाकर तैनात

किया गया। इलाके में लगातार पैदल मार्च और पेट्रोलिंग की जा रही है। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है। पुलिस-प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने और किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा नहीं करने की अपील की है। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान में जुटी है। इसके लिए घटनास्थल और आसपास लगे सीसी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही ड्रोन से भी इलाके की गिरगनी और संदिग्धों की पहचान की जा रही है।

10 श्रेणियों में होंगे ‘विश्व पर्यटन दिवस पुरस्कार-2026

उत्तर बस्तर कांकेर। छत्तीसगढ़ में पर्यटन क्षेत्र को नई पहचान देने, पर्यटन से जुड़े उद्यमियों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों के उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहित करने तथा राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास, संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा ‘विश्व पर्यटन दिवस पुरस्कार-2026’ प्रदान किए जाएंगे। इस पुरस्कार योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले होटल, पंजीकृत टूर ऑपरेटर, जिले, पर्यटन स्टार्टअप, रिसॉर्ट, पर्यटक सूचना केंद्र, होमस्टे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इको-टूरिज्म साइट और एडवेंचर टूरिज्म संचालकों को सम्मानित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत कुल 10 श्रेणियों में एक-एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक विजेता को 11 हजार रूपए की पुरस्कार राशि एवं मेमेंटो प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है विश्व पर्यटन दिवस पुरस्कार-2026’ की खासियत यह है कि इसमें पर्यटन को केवल पर्यटन स्थलों तक सीमित न रखते हुए उससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को भी सम्मान के दायरे में शामिल किया गया है। आतिथ्य, पर्यटन संचालन, जिला पर्यटन प्रबंधन, उद्यमिता, रिसॉर्ट सेवाएं, पर्यटक सहायता, होमस्टे, डिजिटल प्रचार, पर्यावरण संरक्षण और साहसिक पर्यटन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा।

बिलासपुर के रतनपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया

बिलासपुर। रक्षाबंधन की रात दो समुदायों के बीच हुई घटना का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है, इसी बीच महामाया नगरी रतनपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल, 22 अगस्त को मंदिर परिसर में दुकान लगाने वाली महिला और कुछ लोगों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। इसी घटना के विरोध में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठन के दुर्गेश ने कहा कि रतनपुर मां भगवती का क्षेत्र है और आए दिन



इसे असामाजिक तत्वों के लोग दूषित करने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम इकठ्ठा हुए हैं। मंदिर समिति के पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है कि आने वाले समय में ऐसी घटना न हो। पिछले दिनों यहां असामाजिक तत्वों ने हिंदू भाई को मारा। हमने धर्म की है कि मंदिर क्षेत्र सनातन मां के लोगों का है। यहां हिंदुओं को ही

बस्तर के ज्ञानगुड़ी से निकले चार हीरे पहले ही राउंड में एमबीबीएस सीट पक्की

जगदलपुर। बस्तर के दूरदराज अंचलों में छिपी प्रतिभाएं जब सही मार्गदर्शन पाती हैं, तो वे बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर इतिहास रच देती हैं। बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा के मार्गदर्शन में जिला निशुल्क ‘ज्ञानगुड़ी’ कोचिंग संस्थान ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता और उत्कृष्टता साबित की है। संस्थान के चार होनहार विद्यार्थियों ने नीट के पहले ही चरण की काउंसलिंग में सफलता का परचम लहराते हुए प्रतिष्ठित शासकीय कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें सुरक्षित कर ली हैं। इस उपलब्धि के तहत समीर मरकाम और गीतेश्वरी सलाम को शासकीय मेडिकल कॉलेज डिमरापाल जगदलपुर और कुमारी कृष्णा सेन को कांकेर मेडिकल कॉलेज तथा खुशबू बिस्वास को पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर



में प्रवेश मिला है। सफलता की इस ऐतिहासिक घड़ी में चयनित विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर बस्तर कलेक्टर श्री छिकारा से सौजन्य मुलाकात की और अपनी सफलता का श्रेय उनके निरंतर मार्गदर्शन को दिया। कलेक्टर ने विद्यार्थियों के इस असधारण प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी और भविष्य की उच्च शिक्षा में डिजिटल सहायता के उद्देश्य से सभी को टैबलेट

उपहार स्वरूप भेंट किए। इस दौरान उन्होंने सफल छात्रों, उनके शिक्षकों और अभिभावकों की मेहतत की सराहना करते हुए विद्यार्थियों से भावुक अपील की कि वे अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के उपातं वापस बस्तर आकर यहीं के ज़रूरतमंद लोगों और समाज की सेवा में अपना योगदान दें। छात्रों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कलेक्टर श्री

छिकारा द्वारा पूरे वर्ष दिए गए अध्ययन और तैयारी के पिन्-पॉइंट सुझावों ने उनकी रणनीति को मजबूत बनाया, जिसके दम पर वे पहले ही प्रयास में इस प्रतिष्ठित मुकाम तक पहुंच सके। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री छिकारा लगातार ज्ञानगुड़ी केंद्र का दौरा कर स्वयं छात्रों की काउंसलिंग करते रहे हैं और अपनी पढ़ाई व यूपीएससी की तैयारी के व्यावहारिक अनुभवों से उन्हें प्रेरित करते रहे हैं। इसी समर्पित प्रयास का परिणाम है कि संस्थान के 90 में से 50 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की और उनमें से चार बच्चों ने पहले ही राउंड में सीधे एमबीबीएस सीट हासिल कर ली। इस अवसर पर छिटी कलेक्टर हीरा गवर्ना, ज्ञानगुड़ी प्रभारी श्री अलेक्जेंडर एम चेरियन, श्री जी श्रीनिवास राव, श्री मनीष श्रीवास्तव तथा श्री संजीव बिस्वास भी उपस्थित थे।

महतारी वंदन से श्रीमती सीता वर्मा को मिला संबल

महासमुंद। महतारी वंदन योजना ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाई है। महासमुंद्र शहर के वार्ड नंबर 11 की हितप्रार्थी श्रीमती सीता वर्मा की कहानी भी इसी बदलाव का उदाहरण है। योजना के तहत उन्हें अब तक 31वॉर् किश्त प्राप्त हो चुकी है और नियमित रूप से मिलने वाली आर्थिक सहायता ने



उनके परिवार की मुश्किलों को आसान करने में विशेष भूमिका निभाई है। सीता वर्मा बताती हैं कि उनके परिवार में 11 सदस्य हैं। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच आवृत्तिका चलाना चुनौतीपूर्ण था। ऐसे समय में महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली नियमित राशि उनके लिए बड़ा सहारा बनी। उन्होंने इस राशि का उपयोग अपनी आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से सिलाई मशीन खरीदने में किया। सिलाई मशीन मिलने के बाद उन्होंने घर

जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने की चिंता बनी रहती थी, लेकिन नियमित आर्थिक सहायता और सिलाई के काम से होने वाली आय ने उनकी मुश्किलों को काफी हद तक कम कर दिया है। आज वे स्वयं को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ महसूस कर रही हैं।श्रीमती सीता वर्मा ने महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को निरंतर आर्थिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।



श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति

गांव से ग्लोबल कनेक्टिविटी तक

बदलता छत्तीसगढ़

मजबूत सड़कें, विस्तृत रेल नेटवर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी और आधुनिक शहरों के दम पर विकास की नई पहचान गढ़ रहा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ आज विकास के ऐसे दौर से गुजर रहा जहां इंफ्रास्ट्रक्चर केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। गांवों को शहरों से, आदिवासी अंचलों को मुख्यधारा से और प्रदेश को राष्ट्रीय एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए सड़क, रेल, डिजिटल नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स, शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कनेक्टिविटी को विकास की सबसे बड़ी आधारशिला बनाया है। नई सड़कें गांवों तक पहुंच रही हैं, रेल नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, डिजिटल सेवाएं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं और आधुनिक शहरी परियोजनाएं नागरिक सुविधाओं को नई पहचान दे रही हैं। परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ अब केवल खनिज संपदा का राज्य नहीं, बल्कि उभरते हुए औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल हब के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है।

विकसित छत्तीसगढ़ का सपना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कनेक्टिविटी के बिना संभव नहीं है। हमारी सरकार का लक्ष्य केवल सड़क, पुल, रेल लाइन या डिजिटल नेटवर्क बनाना नहीं, बल्कि विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। आज बस्तर के वनांचल से लेकर सरगुजा के गांवों तक और राजधानी रायपुर से लेकर राष्ट्रीय बाजारों तक कनेक्टिविटी का एक नया नेटवर्क तैयार हो रहा है। डिजिटल भारतनेट परियोजना, नए एक्सप्रेस-वे, रेलवे कॉरिडोर, ग्रामीण सड़कें, नगरोत्थान योजना और बस्तर में चल रहे विकास कार्य मिलकर छत्तीसगढ़ को विकसित भारत की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करेंगे। हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ प्रदेश के हर गांव, हर परिवार और हर नागरिक तक पहुंचे।

- श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



सड़कों से खुल रहे विकास के नए द्वार

गांव-शहर की दूरी घट रही,
अवसरों की दूरी मिट रही



- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 2.225 करोड़ रुपए की लागत से 774 नई ग्रामीण सड़कों को मंजूरी।
 - कुल लंबाई 2,426 किलोमीटर।
 - मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के माध्यम से लगभग 1,000 दूरस्थ गांव ने सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जुड़े।
 - शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार तक पहुंच होगी आसान।
- संदेश साफ है, जहां सड़क पहुंचेगी, वहां विकास पहुंचेगा।



एक्सप्रेस-वे से तेज हुई विकास की रफ्तार

उद्योग, व्यापार और निवेश
को मिल रही नई दिशा



- रायपुर-विशाखापटनम एक्सप्रेस-वे और दुर्ग-रायपुर-आरंग एक्सप्रेस-वे प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गलियारों से जोड़ रहे हैं।
- बंदरगाहों तक पहुंच आसान, माल परिवहन सस्ता और उद्योगों को नई प्रतिस्पर्धक क्षमता।
- NH-53 पर रायपुर से विश्वप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल सिरपुर तक यात्रा पहले से अधिक सुगम हुई।



रेलवे क्रांति : नई पटरी पर दौड़ता विकास

22 गुना बढ़ा रेलवे बजट,
बदल रही प्रदेश की तस्वीर



- 2009-14 में रेलवे बजट औसतन 311 करोड़ प्रति वर्ष।
- अब बढ़कर 26,925 करोड़ प्रति वर्ष।
- नई रेल लाइनों, डबलिंग, मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से प्रदेश का रेल नेटवर्क लगातार मजबूत।

मेगा रेल कॉरिडोर : भविष्य की नई धुरी

- खरसिया नया रायपुर-परमलकसा के बीच 28,741 करोड़ की लागत से 5वीं एवं 6वीं रेल लाइन परियोजना जारी।
- दल्लीराजहरा रावघाट-जगदलपुर नई रेल लाइन बस्तर को मजबूत करेगी।



डिजिटल कनेक्टिविटी : गांव-गांव तक इंटरनेट की पहुंच

3,942 करोड़ रुपए की भारतनेट परियोजना
बनेगी डिजिटल जीवनरेखा



- 11,682 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी आधारित हाई-स्पीड डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।
- ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल बैंकिंग और ग्रामीण उद्यमिता को नई ताकत।



अबुझमाड़ तक पहुंची डिजिटल क्रांति

ताहकाडोंड में मोबाइल टावर ने बदली जिंदगी



4G संचुरेशन प्रोजेक्ट से जुड़े दूरस्थ गांव डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग सेवाएं और सरकारी योजनाओं की जानकारी अब सीधे ग्रामीणों तक।



डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का नया केंद्र बन रहा नवा रायपुर

देश का पहला AI आधारित
डेटा सेंटर पार्क



AI, क्लाउड सेवाएं, डेटा प्रोसेसिंग और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को नई पहचान। हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।



लॉजिस्टिक्स और उद्योग में नई उपलब्धि

LEADS रिपोर्ट में 'हाई परफॉर्मर' बना छत्तीसगढ़

- LEADS 2025 रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को 'हाई परफॉर्मर' राज्य का दर्जा
- बेहतर सड़क नेटवर्क, मजबूत परिवहन व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स सुधार
- औद्योगिक विकास नीति 2024-30 और लॉजिस्टिक्स नीति निदेशकों के लिए नए अवसर।



शहरी विकास की नई तस्वीर

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से बदलेंगे शहर

- 13 नगर निगमों में 429.45 करोड़ रुपए की लागत से 26 बड़े प्रोजेक्ट्स मंजूर
- रायपुर में सड़क जंक्शन उन्नयन, जलापूर्ति नेटवर्क विस्तार, महादेव घाट पुनर्विकास, तेलीबांधा में तकनीकी टॉवर निर्माण।
- आधुनिक, व्यवस्थित और नागरिक केंद्रित शहरों की दिशा में बढ़ा कदम।



ऊर्जा और नागरिक सुविधाओं का विस्तार

- नए सब-स्टेशनों और पॉवर नेटवर्क विस्तार से बेहतर और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध।
- शहरों में सड़क चौड़ीकरण, जलापूर्ति, बस टर्मिनल, सार्वजनिक उद्यान और नागरिक सुविधाओं का विस्तार।
- जीवन स्तर में हो रहा उल्लेखनीय सुधार।

बस्तर में विकास का नया अध्याय



कोण्डागांव को मिली 152.19 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक सौगात, 43 विकास कार्य



77 करोड़ की लागत से 8.89 किमी लंबा कोण्डागांव बाईपास



उच्च स्तरीय पुल निर्माण परियोजनाएं



ग्राम पंचायत डिजिटल नेटवर्क से जुड़ेगी



सिंचाई एवं जल संरक्षण कार्य



नए विद्युत उपकेंद्र



महतारी सदन और दीदी की रसोई जैसी परियोजनाएं



स्कूल भवन और ग्रामीण अधीनस्थ विकास

कनेक्टिविटी, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा और ऊर्जा सुविधाओं को मिलेगी नई मजबूती



₹3,942
करोड़ भारतनेट परियोजना



11,682
ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं



₹8,741
करोड़ मेगा रेल कॉरिडोर परियोजना



₹2,225
करोड़ PMGSY 774 नई सड़कें



₹429.45
करोड़ नगरोत्थान योजना



₹152.19
करोड़ कोण्डागांव विकास कार्य

विकसित छत्तीसगढ़ की ओर मजबूत कदम

मजबूत कनेक्टिविटी

आधुनिक अधीनस्थ

डिजिटल सशक्तीकरण

समृद्ध छत्तीसगढ़



रविवि और सीएमडीसी मिलकर खोदेंगे कोरंडम खदान

नया रायपुर में आयोजित क्रिटिकल और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी से जुड़े रोडशो एवं कार्यक्रम के दौरान संपन्न हुआ

रायपुर। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों के दोहन के साथ-साथ उनके स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीजापुर जिले के कुचनूर क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद कोरंडम खदान का पुनः संचालन किया गया है। कोरंडम के खनन से लेकर उसकी कटिंग, पॉलिशिंग, आभूषण निर्माण, ब्रांडिंग और विपणन तक पूरी वैल्यू चेन विकसित करने के उद्देश्य से सीएमडीसी और पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के बीच मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में नया रायपुर स्थित मेफेयर रिजॉर्ट में यह महत्वपूर्ण एमओयू सम्पन्न हुआ। विश्वविद्यालय को नॉलेज

पार्टनर के रूप में चयनित किया गया है, जिसके माध्यम से स्थानीय युवाओं और शिल्पकारों को आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उच्च गुणवत्ता वाले कोरंडम का उत्खनन

प्रदेश में कोरंडम खनिज के दोहन एवं विपणन के लिए छ्छष्ट और संयुक्त उपक्रम साझेदार मेसर्स एन.सी. नाहर के मध्य गठित छत्तीसगढ़ कोरंडम माइन्स लिमिटेड के माध्यम से बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम क्षेत्र के ग्राम कुचनूर में कोरंडम खदान संचालित की जा रही है। लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद फरवरी 2025 से खदान का पुनः संचालन करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले कोरंडम का वैज्ञानिक पद्धति से उत्खनन किया जा रहा है। वर्तमान में खदान से उत्खनित कोरंडम का लगभग 240 किलोग्राम



भंडारण है, जिसमें से 157.643 किलोग्राम का परिवहन किया जा चुका है। परिवहन किए गए कोरंडम में 107.989 किलोग्राम बी-ग्रेड तथा 49.654 किलोग्राम औद्योगिक ग्रेड कोरंडम शामिल है।

खनन के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार

कुचनूर कोरंडम खदान के संचालन से बीजापुर जिले के 14 स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार और छ्छष्ट का प्रयास है कि खनिज आधारित गतिविधियों का लाभ केवल खनन तक सीमित न रहे, बल्कि स्थानीय समुदायों, युवाओं, शिल्पकारों, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों की भागीदारी से आय के नए अवसर सृजित हों।

कटिंग-पॉलिशिंग के प्रशिक्षण से बढ़ेगा मूल्य संवर्धन

कोरंडम से अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर जेम्स्टोन हैंडलिंग, कटिंग, पॉलिशिंग और अन्य वैल्यू एडिशन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को नॉलेज पार्टनर बनाया गया है। आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रबों की पहचान और कौशल गतिविधियों में दक्ष बनाया जाएगा। इससे उन्हें रोजगार के साथ स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के अवसर भी मिलेंगे।

‘बस्तर ब्रांड’ के तहत रत्न उत्पादों को मिलेगा बाजार

कुचनूर से प्राप्त उच्च गुणवत्ता वाले कोरंडम को ‘बस्तर ब्रांड’ के तहत

स्थानीय डिजाइन, गुणवत्ता और प्रमाणिकता से जोड़ने की योजना है। कोरंडम से आभूषण एवं रत्न उत्पाद तैयार कर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे बस्तर की स्थानीय कला, शिल्प और प्राकृतिक खनिज संपदा को एक साथ बाजार से जोड़ने में मदद मिलेगी। स्थानीय इकाइयों, स्टार्टअप्स, शिल्पकारों और निवेशकों की भागीदारी से कोरंडम आधारित नए उद्यम विकसित किए जा सकेंगे।

नए कोरंडम क्षेत्रों की पहचान और अन्वेषण जारी

बीजापुर जिले में कोरंडम से जुड़े नए संभावित क्षेत्रों की पहचान, अन्वेषण एवं पूर्वेक्षण का कार्य भी जारी है। भोपालपट्टनम क्षेत्र में ग्राम कुचनूर सहित अन्य संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर खनन गतिविधियों के विस्तार की दिशा में कार्रवाई की जा

रही है। धनगोल सहित विभिन्न इलाकों में क्षेत्र आरक्षित कर आवेदन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।

बस्तर को मिलेगी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान

उत्खनित कोरंडम की पारदर्शी तरीके से नीलामी से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि के साथ बस्तर क्षेत्र को कोरंडम को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग के साथ स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन होने से खनिज की वास्तविक आर्थिक क्षमता का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। सीएमडीसी की यह पहल ‘खनन से मूल्य संवर्धन, मूल्य संवर्धन से रोजगार और रोजगार से आर्थिक सशक्तिकरण’ की अवधारणा को जमीन पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

शहीद वीर नारायण सिंह का जीवन सेवा, संघर्ष और राष्ट्रप्रेम की मिसाल : अरुण साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने बेमेतरा में शहीद वीर नारायण सिंह की भव्य प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। वे प्रतिमा अनावरण के बाद कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित जिला स्तरीय आदिवासी महासम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम के गांवडवाना भवन के जीर्णोद्धार के लिए 10 लाख रुपए तथा बेमेतरा में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। विधायक श्री दीपेश साहू भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आदिवासी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ की माटी के ऐसे महान सपूत थे, जिन्होंने गरीबों



और जरूरतमंदों की सहायता के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वीरतापूर्वक संघर्ष किया। उनका पूरा जीवन संघर्ष, सेवा और राष्ट्रप्रेम की भावना से भरा रहा। उनके मन में समाज के प्रति सेवा का भाव और मातृभूमि के प्रति गहरा प्रेम था। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में गरीब और शोषित लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। अंग्रेजों के अत्याचार के सामने वे कभी नहीं झुके और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। श्री साव ने कहा कि

छत्तीसगढ़ की धरती अनेक वीर योद्धाओं और जननायकों की गौरवशाली भूमि रही है। शहीद वीर नारायण सिंह और गुंडाधुर जैसे महान योद्धाओं ने अपने साहस से समाज व मातृभूमि के प्रति समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। इन वीर सपूतों का त्याग और बलिदान हमारी आने वाली पीढ़ियों को सदैव याद रहेगा। उन्होंने कहा कि बेमेतरा में स्थापित शहीद वीर नारायण सिंह की यह प्रतिमा उनके त्याग और बलिदान की स्मृति को चिरस्थायी बनाएगी।

18 से 20 सितंबर तक रायपुर में सजेगा 14वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2026

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आगामी सितंबर माह में देश के औद्योगिक परिदृश्य में अपनी एक नई और सशक्त पहचान दर्ज कराने जा रही है। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों , स्टार्टअप्स, नए उद्यमियों, निवेशकों और युवाओं को एक ही मंच पर लाने के उद्देश्य से आगामी 18, 19 और 20 सितंबर 2026 को साईंस कॉलेज ओपन ग्राउंड में भव्य 14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयरका आयोजन किया जा रहा है। लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित यह तीन दिवसीय महाकुंभ प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा।

आयोजन की तैयारियां रायपुर में तेजी से चल रही हैं। हाल ही में लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर फेयर की रूपरेखा और उद्देश्यों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को छत्तीसगढ़ के स्थानीय उद्यमियों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने, आधुनिक तकनीक अपनाने और कारोबार का विस्तार करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की संभावना है। उनके साथ उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं प्रमुख विचातक श्री कृष्ण गोपाल जी की उपस्थिति भी प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय स्तर के नीति-निर्माताओं और उद्योगपतियों के एक मंच पर जुटने से राज्य के औद्योगिक विकास में दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा, कृषि एवं वन उत्पादों से समृद्ध राज्य है। इसके बावजूद राज्य के छोटे और मध्यम उद्यमों के सामने अपने उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने, नई तकनीक हासिल करने और पूंजी निवेश आकर्षित करने की चुनौतियां बनी रहती हैं। इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर इन चुनौतियों को नए अवसरों में बदलने का काम करेगा।

खरगे के रैली स्थल का ‘शुद्धिकरण’ और राहुल पर एफआईआर भाजपाई तानाशाही का प्रमाण : बैज

रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी के रैली स्थल का ‘शुद्धिकरण’ और राहुल गांधी जी पर एफआईआर को भाजपाइयों के तानाशाही चरित्र का प्रमाण बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बर्बर, ओछी और दलित विरोधी मानसिकता का वीभत्स चेहरा एक बार फिर देश के सामने आ गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ दलित नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे जी की जनसभा के बाद भाजपाई नेताओं द्वारा उस सभास्थल का ‘शुद्धिकरण’ कराया जाना केवल खरगे जी का अपमान नहीं, बल्कि देश के करोड़ों दलितों, वंचितों और बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान पर सीधा हमला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी और उसके पिपु संगठन



आरएसएस पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा का असली डीएनए दलित विरोधी है। एक तरफ जहां दलित समाज के शीर्ष नेता का अपमान किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाने वाले हमारे नेता राहुल गांधी जी पर उल्टे झूठी एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक अधिकारों को निर्ममता पूर्वक कुचल रही है यह सरकार।

भाजपा सरकार बताएं कि अपराधियों को किसका संरक्षण है? उत्तराखंड में जुर्म और अत्याचार करने वाले अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने के बजाय भाजपा सरकार उन पर पर्दा डालने में क्यों जुटी है? राहुल गांधी जी से खोफ क्यों? जब भी

राहुल गांधी जी देश के शोषितों, पीड़ितों और दलितों के हक के लिए आवाज बुलंद करते हैं, भाजपा की सत्ता कांपने लगती है। एफआईआर और मुकदमों की राजनीति से राहुल जी और कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। शुद्धिकरण का ढोंग क्यों? खरगे जी जैसे सम्मानित नेता के रैली स्थल का ‘शुद्धिकरण’ करारक भाजपा ने अपनी सामंतवादी और छुआछूत वाली मानसिकता का प्रमाण दे दिया है।

भाजपा और आरएसएस का असली चेहरा अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। इनकी यह ‘इस्तेमाल करो और अपमानित करो’ की नीति अब चलने वाली नहीं है। यह देश और देश की जनता सब देख रही है। इनक तरफ वह ताकतें हैं जो दलितों के हक, सम्मान और संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठा रही हैं, और दूसरी तरफ भाजपा है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

फुटबॉल स्टेडियम के लिए 5.49 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों से जशपुर जिले में खेल अधोसंरचना के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला मुख्यालय जशपुर में आधुनिक फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 करोड़ 49 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण से जशपुर जिले के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही, स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी खेल प्रतिभा निखारने और जिला स्तर से आगे बढ़कर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए बेहतर मंच मिलेगा।जशपुर जिले में फुटबॉल के प्रति खिलाड़ियों और युवाओं में विशेष उत्साह एवं रुचि को देखते हुए यह स्टेडियम खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे जिले में नियमित प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं और खेल आयोजनों के लिए बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध होगा।इच्छेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा जशपुर जिले में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और खेल सुविधाओं के विस्तार पर लगातार जोर दिया जा रहा है।

मंत्रियों का वेतन रोकने का साहस दिखाए सरकार: सूरज



रायपुर । सभी जिलों के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित स्कूल के प्रधानपाठक का वेतन रोकने संबंधी आदेश पर आम आदमी पार्टी मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कड़ी आपत्ति जताई है। शिक्षक संघ ने भी इस आदेश को तुलना की फरमान बताते हुए विरोध किया है।उनका कहना है कि छात्रवृत्ति वितरण एक विभागीय एवं प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें स्कूल स्तर से लेकर विकासखंड, जिला और विभाग स्तर तक कई जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे में पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रधानपाठक के सिर मढ़कर उनका वेतन रोकने की चेतावनी देना न केवल अनुचित है, बल्कि शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।अगर किसी सरकारी योजना या सुविधा का लाभ हितग्राहियों तक नहीं पहुंचने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी का वेतन रोकना ही सरकार की नीति है, तो यह नियम सभी विभागों में समान रूप से लागू होना चाहिए। क्या इसी तरह बदहाल और जर्जर सड़कों के लिए पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारियों का वेतन रोकना जाएगा? बिजली कंपनी में घाटा दिखाने वाले एम डी का वेतन कब रोका जायेगा? बारिश में सड़कें टूट रही हैं, गड्ढों के कारण लोगों की जान जोखिम में है।

मुख्यमंत्री साय ने किया ‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल का शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नया रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पात्र हितग्राहियों को नि:शुल्क रेत उपलब्ध करने के लिए ‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण में हितग्राहियों को रेत की उपलब्धता आसान बनाना और उनके पक्के घर के सपने को साकार करने में सहयोग देना है।‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल के माध्यम से पीएमएवाय-जीके पात्र हितग्राहियों को नि:शुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी। पोर्टल पर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, जिससे रेत की मांग, स्वीकृति एवं उपलब्धता की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। इससे हितग्राहियों को रेत प्राप्त करने के लिए अनावश्यक भागदौड़ और प्रक्रियागत कठिनाइयों से राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। आवास निर्माण में रेत एक महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है। ऐसे में पात्र हितग्राहियों को नि:शुल्क रेत उपलब्ध कराने की यह व्यवस्था उनके निर्माण खर्च को कम करने में सहायक होगी और आवास निर्माण को गति मिलेगी। ‘ई-रेत संगवारी’ के माध्यम से सरकार ने आवास योजना के लाभ को निर्माण सामग्री की सुविधा से जोड़ते हुए हितग्राहियों को अतिरिक्त सहयोग उपलब्ध कराया है।

छत्तीसगढ़ आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर: शुक्ला

रायपुर। भारत सरकार के नीति आयोग की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की वित्तीय व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नीति आयोग ने देश के 18 राज्यों के वित्तीय स्थिति के बारे में जो रिपोर्ट जारी



किया है। उसमें छत्तीसगढ़ 17वें नंबर पर है। राज्य का राजकोषिय घाटा तय लक्ष्य 2.99 से बढ़कर 5.32 हो गया है। नीति आयोग के अनुसार छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिती दिवालियो होने की है। सरकार इस रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण जारी करे। यह रिपोर्ट प्रदेश के विकास के लिये चिंताजनक है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारत सरकार के नीति आयोग की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट यह प्रमाणित करती है कि भाजपा सरकार और वित्तमंत्री ओपी चौधरी वित्तीय अनुशासन और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। केंद्र सरकार के ताजा रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का राजकोषीय अनुशासन स्कोर महज एक साल में 56 से गिरकर 7.4 अंक रह गया है। 18 बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ अब 17वें स्थान पर पहुंच चुका है, अर्थात नीचे से दूसरे स्थान पर।

प्रमोद गुरु बाला पीर धाम में संध्या आरती का आयोजन



रायपुर। महादेव घाट स्थित प्रमोद गुरु बाला पीर धाम में चौदस पूर्णिमा के पावन अवसर पर संध्या आरती का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महानगर अध्यक्ष मोतीदास मानिकपुरी के मार्गदर्शन में महंत बी.डी. मानिकपुरी, दिवान जगमोहन दास मानिकपुरी एवं मनहरण दास की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में महंत बी.डी. मानिकपुरी ने अपने प्रवचन में सद्गुरु कबीर साहेब के चारों युगों में मानव समाज के कल्याण एवं उद्धार के लिए अवतीर्ण होने के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। तत्पश्चात महंत, दिवान एवं साधु-संतों द्वारा कबीर साहेब के समुधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित सामाजिक जनों ने इस संध्या आरती के कार्यक्रम को प्रतिमाह अनवरत रूप से जारी रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर छ.ग. मानिकपुरी पनिका समाज की महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वरी मानिकपुरी, प्रवक्ता मनोज मानिकपुरी, युवा सहसचिव पुरुषोत्तम (रिंकू) मानिकपुरी, रोम दास मौजूद थे।

पहले ही राउंड में एमबीबीएस सीट हासिल कर रवा गौरव

बस्तर की ‘ज्ञानगुड़ी’ से निकले चार हीरे

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है तो केवल उन्हें सही दिशा, गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराने की। बस्तर जिला प्रशासन द्वारा इसी सोच के साथ संचालित नि:शुल्क ‘ज्ञानगुड़ी’ कोविंग संस्थान आज प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की एक प्रेरक मिसाल बनकर उभर रहा है। संस्थान के चार होनहार विद्यार्थियों ने नीट की काउंसलिंग के पहले ही राउंड में शासकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीट हासिल कर बस्तर का नाम रोशन किया है।



ज्ञानगुड़ी के विद्यार्थियों की यह सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपलब्धि उन युवाओं ने हासिल की है, जो बस्तर के दूरस्थ अंचलों से आते हैं और जिन्हें बेहतर उच्च शिक्षा के लिए महानगरों जैसी सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध नहीं थीं।

जिला प्रशासन की पहल, शिक्षकों के समर्पित प्रयास और विद्यार्थियों की कठिन मेहनत ने इन परिस्थितियों को अवसर में बदल दिया।चार विद्यार्थियों को मिली एमबीबीएस में प्रवेश की सफलता के तहत समीर मरकाम और गीतेश्वरी सलाम का चयन

शासकीय मेडिकल कॉलेज, डिमरापाल जगदलपुर, कुमारी कृष्णा सेन का कंकर मेडिकल कॉलेज तथा खुशबू बिस्वास का पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में हुआ है।

पहले ही राउंड में शासकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलना विद्यार्थियों की उत्कृष्ट तैयारी और ज्ञानगुड़ी की प्रभावी शैक्षणिक व्यवस्था का प्रमाण है। 90 में से 50 विद्यार्थियों ने नीट में पाई सफलता: ज्ञानगुड़ी की उपलब्धि केवल चार एमबीबीएस चयन तक सीमित नहीं है। संस्थान में 50 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा

उत्तीर्ण की है। इनमें से चार विद्यार्थियों ने काउंसलिंग के पहले ही चरण में सीधे एमबीबीएस की सीट हासिल की है। यह परिणाम बताता है कि यदि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, अध्ययन सामग्री और निरंतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए, तो वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी किसी से पीछे नहीं हैं।सफल विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकरा से सौजन्य मुलाकात की। विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय जिला प्रशासन के निरंतर सहयोग और कलेक्टर के मार्गदर्शन को दिया।



तिलक वर्मा थाना तेलीबांधा, आरक्षक 213 वार्डका चौहान थाना कोतवाली, आरक्षक 2135 वासुदेव कोसरिया थाना मोदहापारा, आरक्षक 1936 नरेंद्र यादव थाना गुडियारी, आरक्षक 2160 जयप्रकाश चौधरी थाना उरला, आरक्षक 1038 रामकिंकर गावड़ थाना खमतगाई, आरक्षक 2629 रामचरण ध्रुव चौकी रामनगर, आरक्षक 442 राजेश खलखो थाना पण्डरी, आरक्षक

2029 उमेश कुमार थाना खम्हारडीह, आरक्षक 2075 हरीश धुव थाना टिकरापारा, आरक्षक 404 भूवाम्बु नाथ थाना टिकरापारा, आरक्षक 1153 डाकेश्वर साहू थाना डी.डी. नगर, आरक्षक 2206 चंद्रकिशोर गायकवाड थाना डी.डी. नगर, आरक्षक 1356 होरीलाल बारले थाना डी.डी. नगर, आरक्षक 2070 डोमन लाल नवरंग थाना डी.डी. नगर, आरक्षक 2728 यदुनाथ पटेल थाना पुरानीबस्ती, आरक्षक 534 लोकनाथ दीवान थाना पुरानीबस्ती, आरक्षक 717 विकास श्रीवास्तव थाना मुजगहन तथा आरक्षक 2776 रितेश कुमार ध्रुव को थाना मुजगहन में पदस्थ किया गया है।